RNI No. : MPHIN/2010/38129 MP/IDC/1375/2020-22 www.hariyalikerastey.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 9 » जुलाई 2020 » मूल्य : 40 रु.

Email : hariyalikeraste2010@gmail.com

शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार

गेहूँ उपार्जन में नंबर-1 बना म.प्र.

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर
माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान
को हार्दिक शुभकामनाएँ
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी
किसान भाइयों को शुभकामनाएँ
श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्रीमती भारती शेखावत
(उपायुक्त सहकारिता)
श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. धार

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी
किसान भाइयों को हार्दिक बधाइयाँ
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान
को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ
किसानों को % ब्याज पर ऋण
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री एम.एल. गजभिये
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री एस.के. खरे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि., इंदौर

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 9 » जुलाई 2020 » मूल्य : 40 रु.

» विशेष संरक्षक : जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनन्त श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज
» संरक्षक : विष्णु नारायण त्रिपाठी
» प्रधान संपादक : बृजेश त्रिपाठी
» प्रबंध संपादक : अर्चना त्रिपाठी
» सलाहकार मंडल :
व्ही.जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त सचिव एवं आयुक्त सहकारिता)
एल.डी. पंडित (सहकारी विशेषज्ञ)
सुशील मिश्र (पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता)
मणिशंकर उपाध्याय (कृषि विशेषज्ञ)
एम.एस. भटनागर (कृषि रत्न, बीज विशेषज्ञ, सलाहकार बीज संघ)
सुरेशचंद्र ताम्रकर (वरिष्ठ पत्रकार)
डॉ. आर.ए. शर्मा (पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर)
डॉ. वी.एन. श्रॉफ (कृषि वैज्ञानिक)
यशोवर्धन पाठक (व्याख्याता जबलपुर)
पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' (अध्यक्ष, म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद)
डॉ. राजीव शर्मा (प्रोफेसर एवं कवि, इंदौर)
डॉ. भरत शर्मा (समाजसेवी)
हरप्रसाद मोदी (वरिष्ठ पत्रकार, झाँसी-ललितपुर)
अरुण के. बंसल (फ्यूचर पॉइंट प्रा.लि., नई दिल्ली)
पं. रतन वशिष्ठ (ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक)
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय (वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य)
कैप्टन (डॉ.) लेखराज शर्मा (ज्योतिषाचार्य)
» विशेष संवाददाता
इंदौर-उज्जैन संभाग : परीक्षित शर्मा (मो. 7999692727)
भोपाल संभाग : आलोक मालवीय (मो. 9806750146)
होशंगाबाद संभाग : धनराज मालवीय (मो. 9827744248)
छत्तीसगढ़ (रायपुर) : पी.एल. चुरहे (मो. 7389652211)
» प्रकाशक : बृजेश त्रिपाठी
306/ए-ब्लॉक, शहनाई-।। रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186
» लेआउट-डिजाइन : नितिन पंजाबी (मो. 9893126800)
ई-मेल : nitinpunjabi5@gmail.com
» मुद्रक : वी.एम. ग्राफिक्स
के-29, एल.आय.जी. कॉलोनी, इंदौर

3
सीमा पर समाधान का समय

5
आत्मनिर्भर भारत ही असली जवाब

8
डराएगा कोरोना डरना नहीं

16
भारत में सहकारिता आंदोलन

22
यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं

24
नए दौर में मध्यप्रदेश के किसान

28
किसानों के लिए सामायिक सलाह

60
'फेयर' शब्द हटाने से बिपाशा खुश

सहकारिता की स्वच्छता के प्रयास

शहरी क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने इन पर नकेल कसने का कदम उठाया है। इस समय देश में 1540 शहरी सहकारी बैंकों से 8.6 करोड़ से अधिक ग्राहक जुड़े हैं। इन बैंकों में 4.85 लाख करोड़ रुपये की पूँजी जमा है। पिछले कुछ दिनों से अनेक शहरी सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए हैं। जमाकर्ताओं में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही थी। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ये बैंक थोड़ी ब्याज दर ऊँची रखते हैं। इस लालच में कि ब्याज ज्यादा मिलेगा, लोग इन बैंकों में अपनी मेहनत की कमाई जमा करा देते हैं। अधिकांश ऐसी बैंकें राजनेताओं के भाई-भतीजों द्वारा संचालित की जाती हैं और कर्ज देने में भी पक्षपात किया जाता है। रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होने से अभी तक इन बैंकों में मनमानी चल रही थी, मगर अब सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद ये बैंकें ऐसा नहीं कर पाएँगी। पीएमसी बैंक में अनियमितताओं की शिकायतों के चलते केन्द्रीय बैंक ने 23 सितंबर 2019 को इस पर नियामकीय अंकुश लगा दिये थे। इसी तरह की कार्रवाई पीपुल्स सहकार बैंक कानपुर के खिलाफ भी की गई थी। आपको याद होगा कि 3 मार्च 2020 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक 2020 पेश किया था। यह विधेयक अभी लंबित है। इस संशोधन विधेयक के जरिए रिजर्व बैंक के बैंकिंग नियामक दिशा-निर्देशों को सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाएगा। निश्चय ही इससे सहकारी बैंकों के घोटालों पर अंकुश लगेगा और जमाकर्ताओं की राशि सुरक्षित रहेगी। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी इसका जिक्र किया था। 24 जून की बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है क्योंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जब संसद सत्र शुरू होगा तो विधेयक पारित कराया जाएगा। जुलाई माह में हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह मनाया जाता है। सहकारिता सप्ताह के पूर्व केन्द्र सरकार की सहकारिता को यह एक अच्छी सौगात है। इससे शहरी सहकारी बैंकों के कार्य में निश्चय ही पारदर्शिता आएगी। भारत में आजादी से पूर्व चल रहा सहकारिता आंदोलन एक विराट स्वरूप लेकर वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा समान उद्देश्य और हित को लेकर किये गये प्रयास ही सहकार या सहकारिता है। बिना एक-दूसरे के सहयोग के जीवन की गाड़ी चलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कृषि और सहकारिता गाड़ी के दो पहियों की तरह है। सहकारिता जगत देश के विकास में आज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। शहरी के अलावा ग्रामीण सहकारी बैंकों और सहकारी सोसायटियों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। बगैर सहकारिता के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी संकट के बावजूद समर्थन मूल्य पर गेहूँ और अन्य उपज का रिकॉर्ड तोड़ उपार्जन हमार सहकारी जगत की एक अनूठी मिसाल है। इतने बड़े जोखिम के बीच सहकारी क्षेत्र के मित्रों ने जो भूमिका अदा की उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। इसलिए तो कहा जाता है **''बिना सहकार नहीं उद्धार''**।

बृजेश त्रिपाठी

सीमा पर समाधान का समय

» पी.जे.एस. पन्नू
डिप्टी चीफ, इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ

अपनी युवावस्था में मैंने मैकमोहन रेखा पर लंबी दूरी के गश्ती दल का नेतृत्व किया है। एक बार हमारे दल को खांगला जाना था। हमें देर हो गई और शाम गहराने लगी थी, लेकिन हमें अपना काम पूरा करना था। गश्ती के दौरान भटककर हम सीमा के उस पार करीब एक किलोमीटर तक चले गए थे। हमने अपने दल को दो टीमों में बांटा और चीनी सैनिकों की नजर में आए बिना हम अगली सुबह खांगला पहुंच गए। एक युवा अधिकारी के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से यह मेरा पहला परिचय था। बाद में मैंने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी डिवीजन और उसके बाद लद्दाख में 14वीं कोर की कमान संभाली। मैं कई बार गलवान घाटी से गुजर चुका हूं। यहां की पर्वत शृंखलाओं पर सीमा-रेखाएं एक भूलभुलैया हैं। यहां न कोई सीमा-रेखा है और न सीमा के करीब कोई पोस्ट। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की जो सीमा-रेखा, यानी एलएसी है, वह 1962 की खूनी जंग का नतीजा है। यह युद्ध दोनों देशों के बीच में यहीं सबसे ऊबड़-खाबड़ और असह्य इलाके में लड़ा गया था। लड़ाई अक्तूबर-नवंबर में दौलत बेग ओल्डी (डीबीओ), गलवान और हॉट स्प्रिंग्स, पैंगोंग झील के आर-पार, रजांगला और डेमचोक इलाकों में हुई थी। अत्यधिक कम तापमान और जान-माल की व्यापक क्षति के कारण उस युद्ध को रोक दिया गया था और चीन के सैनिक अपने ठिकानों पर वापस चले गए थे। इसी तरह, भारतीय सेना भी पास के ठिकानों पर लौट आई थी। तब से राजनीतिक तौर पर औपचारिक सीमांकन न हो पाने की वजह से दोनों देशों की सेनाएं यहां डटी हुई हैं। दोनों के बीच में सीमा-बंटवारे को लेकर 22 बार बातचीत हो चुकी है, पर नतीजा अब तक सिफर रहा है। भारत पूरे अक्साई चिन पर अपना दावा जारी रखे हुए है, तो चीन सीमा के पास वाले क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जिसे भारत 'चीनी धारणा' वाली सीमा रेखा कहता है।

दरअसल, अंग्रेजों ने इन सीमाओं को तय किए बिना छोड़ दिया था। उसके नक्शे में कई सीमाएं दिखाई देती हैं, जिनमें से एक कुन-लुन पहाड़ों के साथ चल रही है, जिसे जॉनसन-अर्दग रेखा कहा जाता है। इसके मुताबिक, अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है। एक अन्य रेखा, जो काराकोरम रेंज के करीब है, उसे मैकार्टनी-मैकडोनाल्ड रेखा कहा जाता है। एक रेखा सुदूर पश्चिम में है, जो फॉरेन ऑफिस रेखा है। आजादी के बाद इसे तय करने का काम जम्मू और कश्मीर के शासकों, तिब्बत और भारत व चीन के हुक्मरानों पर छोड़ दिया गया था। मगर अब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।

भारत ने अपना नक्शा 1954 में ही जारी कर दिया था,

जिसमें अंतरराष्ट्रीय रेखा बताती है कि अक्साई चिन भारत का हिस्सा है। फिर भी, चीन ने 1955 में यहां से गुजरता हुआ पश्चिमी राजमार्ग बनाया, जो तिब्बत को काशगढ़ और शिनजियांग से जोड़ता है। जैसा कि भारत का दावा है, चीनियों ने इस संवेदनशील राजमार्ग के पश्चिमी हिस्से को सुरक्षित रखने की सोची होगी। चिप-चाप नदी और गलवान नदी के जलक्षेत्रों के बीच काराकोरम रेंज के साथ चलने वाली रिज लाइनों पर प्रभावी होने से चीन की यह मंशा बखूबी पूरी हो सकती थी, और उसके बाद चांग-चेनमो रेंज के पश्चिम में रिज लाइनों के साथ दक्षिण-पूर्व में आगे बढ़ना उसके मुफीद होता। इन इलाकों को अपने कब्जे में रखने की कोशिश चीन इसलिए करता है, ताकि भारतीय सुरक्षा बलों को पश्चिमी राजमार्ग से दूर रखा जा सके। यहां आर्टिलरी और निगरानी का दायरा बढ़ाना बताता है कि वह अपनी रेखा को आगे बढ़ाकर पश्चिम की तरफ ले जाना चाहता है। मगर भारतीय सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा में किए जाने वाले किसी भी बदलाव को रोकने के लिए संकल्पित है। उल्लेखनीय है कि एलएसी का पहली बार इस्तेमाल खुद चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने साल 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्र में किया था।

एलएसी को लेकर न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही जमीन पर सीमांकन। यह नक्शे पर मोटी कलम के साथ खींची गई रेखा है। इससे जमीन पर 100 मीटर तक अंतर हो सकता है, इसीलिए रेखा के इस पार या उस पार कुछ मीटर की दूरी पर बना टेंट भी समस्या पैदा कर सकता है।

आज, पूर्वी लद्दाख में 800 किलोमीटर से अधिक सीमा-रेखा है, जिसमें लगभग 550 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। चीनी गश्ती दल यह सुनिश्चित करते हैं कि वे दर्रे को बंद और जलग्रहण क्षेत्र को अपने कब्जे में रखें, ताकि भारतीय सैनिक जमीन पर और आगे न बढ़ सकें। वे ऐसे ट्रैक बनाते रहते हैं, जो आमतौर पर पश्चिमी राजमार्ग से निकलते हैं और उत्तरोत्तर एलएसी की ओर बढ़ते हैं, ताकि वे दर्रे या क्रॉसिंग प्वॉइंट पर हावी हो सकें। हॉट स्प्रिंग्स और गलवान में दोनों तरफ सड़कें व ट्रैक बनाए गए हैं। चीन को इस इलाके का ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उसकी तरफ यह अपेक्षाकृत खुला व समतल है और अपने पश्चिमी राजमार्ग की सुविधा भी उसे हासिल है।

एलएसी को लेकर न तो कोई सर्वे हुआ है और न ही जमीन पर सीमांकन। यह नक्शे पर मोटी कलम के साथ खींची गई रेखा है। इससे जमीन पर 100 मीटर तक अंतर हो सकता है, इसीलिए रेखा के इस पार या उस पार कुछ मीटर की दूरी पर बना टेंट भी समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि, चीन के सैनिकों ने एलएसी के पास जहां तंबू गाड़ा, वहां से गलवान नाला सीधे दिखाई देता है, जहां भारत के लिहाज से संवेदनशील दरबूक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी रोड जाती है, इसीलिए यह भारत को नागवार गुजरा है। इस तरह के मामलों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। साल 1996 में हुआ एक समझौता कहता है कि इस तरह के सीमा-विवादों के निपटारे में सैन्य हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा।

चूंकि सीमा को लेकर अब तक अंतिम सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। इनमें साल 2013 में पूर्वी लद्दाख के डेपसांग, डेमचोक और चुमार में हुआ तनाव भी एक है। गलवान हालिया घटनाओं का चरम बिंदु है। इसका खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के पास परमाणु हथियारों से संपन्न बड़ी सेनाएं हैं। क्या दोनों देश अभी युद्ध का जोखिम उठा सकते हैं, जब पूरी दुनिया के साथ वे भी कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं? बहस का मुद्दा यह भी है कि चीन इस समय ऐसा कोई तनाव क्यों चाहेगा?

समाधान

आत्मनिर्भर भारत ही असली जवाब

» **विवेक काटजू**
पूर्व राजदूत

भारत और चीन का आपसी रिश्ता एक नाजुक, गंभीर और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और देश के सामने बड़ा सवाल यही है कि गलवान घाटी में जो ताजा हिंसक झड़प हुई है, जिसमें हमारे 20 अफसर और जवान शहीद हुए, उसका किस तरह से जवाब दिया जाए? आगे की हमारी चीन-नीति क्या हो? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें भारत-चीन संबंधों की हकीकत और पृष्ठभूमि पर गौर करना होगा।

सच्चाई यही है कि आजादी मिलने के बाद से ही चीन हमारे लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती रहा है। इस सच की अनदेखी 1950 के दशक में भारत सरकार ने की। तब हमारा मानना था कि दोनों देश विकासशील हैं, इसलिए उनके हितों में समन्वय बनाया जा सकता है। मगर भारत जहां शांति के पथ पर चल रहा था, वहीं चीन ने अक्साई चिन को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारों की मानें, तो उस वक्त बीजिंग सीमाओं को लेकर भारत से समझौता करना चाहता था, लेकिन भारतीय हुकूमत का अपनी भूमि से कोई समझौता न करना एक स्वाभाविक कदम था। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, जिसमें हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध सीमित हो गए। इस बीच चीन ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए, ताकि इस्लामाबाद की नई दिल्ली के प्रति पारंपरिक दुश्मनी का वह फायदा उठा सके। उसने पाकिस्तान की आर्थिक-सामरिक ताकत को मजबूत किया, यहां तक कि उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को भी बुनियादी तौर पर सहायता पहुंचाई। आज भारत को चीन-पाकिस्तान के इसी गठजोड़ का मुकाबला करना है।

अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए हमें चीन के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की भी समीक्षा करनी होगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान पर संजीदगी से आगे बढ़ना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश को आगे ले जाना ही होगा।

चीन-भारत युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दो बड़ी हिंसक घटनाएं हुई हैं। पहली वारदात साल 1967 में सिक्किम में हुई, जिसमें हमारे 88 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों की जान गई। दूसरी झड़प 1975 में अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। उसमें असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया गया था। इसके बाद बीते 45 वर्षों में गलवान घाटी की घटना से पहले भारत और चीन के सैन्य 'गश्ती' दल में आपसी टकराव तो हुए, लेकिन किसी सैनिक ने जान नहीं गंवाई।

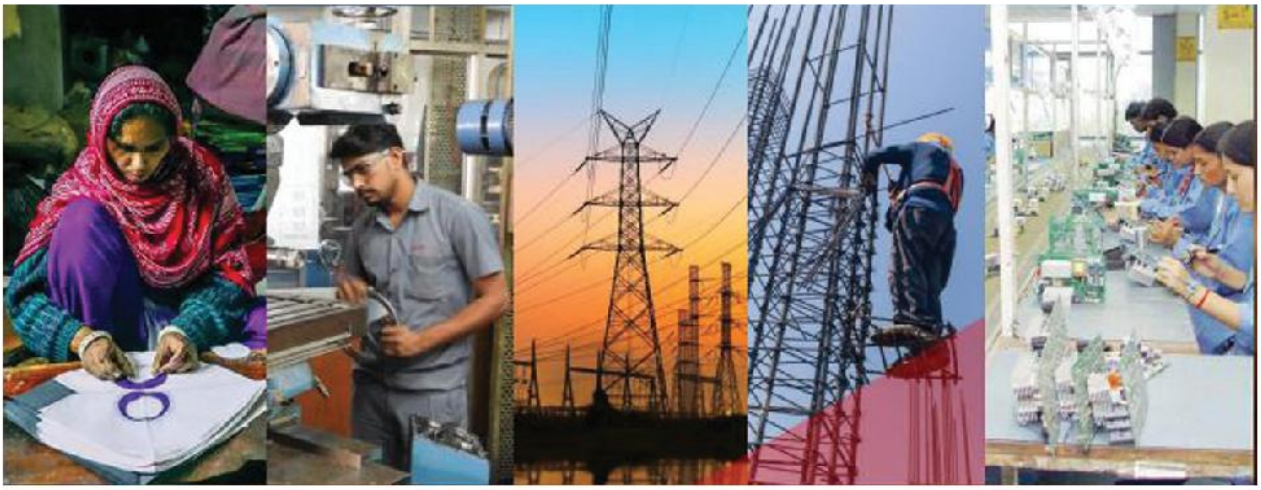

दरअसल, वर्ष 1988 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री-काल में भारत ने अपनी चीन-नीति बदली। यह तय किया गया कि बीजिंग के साथ सीमा-विवाद सुलझाने की कोशिश तो होगी, लेकिन साथ-साथ तमाम क्षेत्रों में उसके साथ आपसी सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। तब से अब तक हर भारतीय हुकूमत ने कमोबेश इसी नीति का पालन किया है। यही कारण है कि आज भारत और चीन के आर्थिक व व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत व व्यापक हो गए हैं। दिक्कत यह रही कि 1988 की नीति में सीमा-विवाद सुलझाने की बात तो कही गई, लेकिन चीन ने कभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि, 1993 के बाद दोनों देशों ने यह तय किया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति के लिए वे आपस में विश्वास बहाली के ठोस उपाय करेंगे। फिर भी, समय-समय पर चीन का रवैया बदलता रहा। यहां तक कि नियंत्रण रेखा को लेकर उसने अपना रुख अब तक स्पष्ट नहीं किया है। इसी वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई स्थानों पर दोनों देशों की सोच एक-दूसरे से अलग है, और दोनों के सैन्य दल आपस में गुत्थमगुत्था हो जाते हैं।

तो क्या 1988 से चल रही हमारी चीन-नीति पर अब पुनर्विचार करने की जरूरत है? यह तभी हो सकता है, जब भारत सरकार ही नहीं, पूरी सामरिक और राजनीतिक बिरादरी में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ एकजुटता बने। बेशक 1978 में अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के बाद चीन ने बहुत तरक्की कर ली है। उसने मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इतनी ताकत हासिल कर ली है कि उसे 'दुनिया की फैक्टरी' कहा जाने लगा है। वहां न सिर्फ हर तरह के उत्पाद बनने लगे हैं, बल्कि उनकी दुनिया भर में आपूर्ति भी होने लगी है। मगर यह भी सच है कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण और अंतरराष्ट्रीय नियमों की उसके द्वारा की जा रही अनदेखी को देखते हुए पूरी दुनिया चिंतित है और कई देशों ने आपसी सहयोग बनाना शुरू कर दिया है।

हरेक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह हम भी अपनी कूटनीति खुद तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपने हितों का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है।

हाल के वर्षों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जिस तरह से आपस में रिश्ते बढ़ाए हैं, उससे भी चीन को ऐतराज है। इन चारों देशों का यह सहयोग अब सामरिक स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, इस चतुष्कोणीय संबंध, यानी क्वाड के साथ-साथ रूस और चीन के साथ मिलकर भारत त्रिपक्षीय बातचीत भी कर रहा है, जिसका स्पष्ट संदेश है कि नई दिल्ली अपने हितों की रक्षा के लिए हर देश से संबंध बढ़ाना चाहती है। भारत बेशक अमेरिका के करीब जाता दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम वाशिंगटन के पिछलग्गू बनकर बीजिंग का विरोध करने को तैयार हैं। हरेक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह हम भी अपनी कूटनीति खुद तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपने हितों का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है।

जाहिर है, चीन की ताजा हिंसक कार्रवाई का हमें पूरी दृढ़ता के साथ मुकाबला करना होगा। हाल की घटनाओं को देखकर यही लगता है कि चीन हर हाल में भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कम करना चाहता है। लेकिन हमें हर तरीके से अपने मान-सम्मान की हिफाजत करनी है। इसके साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव लाने की बीजिंग की हरेक कोशिश को भी नाकाम करना होगा, और हमें ऐसे उपाय भी करने पड़ेंगे कि वह मई, 2020 से पहले की स्थिति में लौटने को मजबूर हो। अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए हमें चीन के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की भी समीक्षा करनी होगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान पर संजीदगी से आगे बढ़ना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में देश को आगे ले जाना ही होगा।

मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान को हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री एम.एल. गजभिये
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री एस.के. खरे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अन्तराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना
सौजन्य से : श्री प्रवीणकुमार जैन (शा.प्र. गाँधीनगर), श्री सुरेंद्र सिंह सिसौदिया (पर्य. गाँधीनगर),
श्री इंदरसिंह मंडलोई (शा.प्र. साकेत नगर), श्री सत्यनारायण जोशी/श्री महावीर शाक्य (पर्य. साकेत नगर),
श्री अंबाराम मालवीय (शा.प्र. खुड़ैल), श्री विजयकुमार वर्मा (पर्य. खुड़ैल)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बड़ा बांगड़दा, जि.इंदौर
श्री गुलाबसिंह डाबी (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बुरानाखेड़ी, जि.इंदौर
श्री मुकेश मौर्य (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिंहासा, जि.इंदौर
श्री सुरेंद्रसिंह सिसौदिया (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सेमल्याचाऊ, जि.इंदौर
श्री शील कुमार (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पालाखेड़ी, जि.इंदौर
श्री सुनील शुक्ला (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पेड़मी, जि.इंदौर
श्री महेश चौधरी (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जम्बुर्डी हप्सी, जि.इंदौर
श्री मनोज दुबे (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कम्पेल, जि.इंदौर
श्री महेश चौधरी (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कनाड़िया, जि.इंदौर
श्री रमेश परमार (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खुड़ैल बुजुर्ग, जि.इंदौर
श्री विजय वर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गारीपिपल्या, जि.इंदौर
श्री महावीर शाक्य (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बावल्याखुर्द, जि.इंदौर
श्री विजय वर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भिचौली मर्दाना, जि.इंदौर
श्री सतीशजी (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. शिवनी, जि.इंदौर
श्री केदार पटेल (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खजराना, जि.इंदौर
श्री सत्यनारायण जोशी (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धमणाय, जि.इंदौर
श्री अनिल तंवर (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. तलावलीचांदा, जि.इंदौर
श्री संतोष चौहान (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पिवड़ाय, जि.इंदौर
श्री सुभाष मंडलोई (प्रबंधक)
प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. श्रीराम पानोड, जि.इंदौर
श्री ज्ञानसिंह तोमर (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

डराएगा कोरोना, डरना नहीं

» घनश्याम बादल

तमाम कोशिशों, सावधानियों के बावजूद भारत में कोरोना का बम फट चुका है और उसका विकिरण पूरी गति के साथ बढ़कर लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके बहुत जल्द ही देश से समाप्त होने के कोई आसार नहीं है और इन्हीं संकेतों को समझते हुए एक और जहां सरकार ने अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या और आने वाले समय में इसके विस्फोट होने की आशंका के चलते हुए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वेंटिलेटर एकत्र करने पर जोर लगा दिया है। साथ ही साथ एक वैचारिक संकीर्णता भी इन दिनों देखने में आई है जिनके चलते विभिन्न राज्यों की सरकारें अब केवल अपने राज्य के निवासियों के लिए ही उन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के संकेत देने लगी है।

यद्यपि मजदूरों एवं प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होने के बाद होने वाला माइग्रेशन अब पूरा हो गया है और जिसे जहां जाना था वह वहां पहुंच गया है, लेकिन वहां पहुंच कर भी इस वर्ग को कोई खास राहत मिलती नहीं दिख रही है। कहीं 7 दिन तो कहीं 14 दिन क्वॉरेंटाइन कॉल इन्हें भारी पड़ रहा है। इनमें रहने वाले लोगों के सैंपल एकत्र करने की एक मजबूत एवं सिस्टमैटिक प्रणाली का न होना, सैंपल्स की रिपोर्ट आने में लगने वाली देरी, इन केंद्रों में भोजन एवं रहने की सुविधाओं का अभाव है। मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड एनालिसिस सर्वे की मानें तो अभी भी भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ लीनियर यानी रेखीय ग्राफ की शक्ल में चल रहा है और यदि सर्वे में शामिल में न की जाने वाली अनापेक्षित घटनाएं जैसे जनसंख्या की वृद्धि, अन्य बीमारियों से होने वाली मौतें, अचानक होने वाला प्रवास, अचानक कहीं भीड़ का इकट्ठा होना, कहीं दंगे हो जाना या फिर अन्य वजहों से सोशल डिस्टेंस का पालन न हो पाना यथास्थिति में रहती हैं तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का चढ़ाव सितंबर के महीने में भी देखना होगा।

विशेषज्ञों की राय है कि यह वायरस तब जाकर समाप्त होगा जब इससे संक्रमित होने वाली लोगों की संख्या इसी वायरस की वजह से ठीक होने वाले लोगों या मरने वाले लोगों के योग के बराबर हो जाएगी। तब इसका ग्राफ ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। इन हालातों में सितंबर 2020 के मध्य तक तो कोरोना वायरस के समाप्त होने की आशा कम ही है। अगर विश्व में मुख्य रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित देशों के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 69 लाख 52 हजार के पार पहुंच गए हैं। अब तक दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेताया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान एक दशक तक रहने की आशंका है।

उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों के संक्रमित होने के समाचार मिले हैं। हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब कोरोना वायरस वीआईपी गैलरी में भी घुस गया है। पहले जहां इस वायरस के संक्रमण से मुख्य रूप से महानगर एवं बड़े शहर ही संक्रमित दिखाई दे रहे थे वही मजदूरों के प्रवास के बाद से यह कस्बों से होता हुआ गांवों तक भी जा पहुंचा है या तो हम सामुदायिक संक्रमण में प्रवेश कर गए हैं अथवा बिल्कुल इस के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग तीन लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं हालांकि 145000 से अधिक ठीक भी हुए हैं और लगभग 9000 लोगों की जाने भी गई हैं। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पता चलता है कि संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर लगभग 11,000 प्रतिदिन पर पहुंच गया है। अब आंकड़ों में भले ही दुगने होने के दिनों की संख्या 12 या 13 हो, लेकिन यदि केवल संख्या पर गौर करें तो यह लगातार बढ़ रही है और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दो हफ्तों में ही यदि परिस्थितियां न बदली तो हर रोज लगभग 20 से 25000 लोग संक्रमित होंगे। ऐसी स्थिति में देशभर के अस्पताल संक्रमित लोगों से भरे नजर आएंगे। तब एक भय जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका है।

यद्यपि सरकारें पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं जुटा लेने का दावा कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार जो बता रहे हैं, उसके अनुसार अस्पताल संक्रमित लोगों को भर्ती करने की बजाय दूसरी जगह रेफर करने की प्रवृत्ति पर चलते दिखाई दे रहे हैं। कभी ऑक्सीजन या वेंटीलेटर न होने जैसी बातें बताकर उन्हें दूसरी जगहों का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से निजी अस्पताल भी संक्रमण होने के लक्षण दिखने पर मरीजों से बचने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। वह सीमित संसाधन होने का बहाना बनाकर मरीजों को टाल रहे हैं। अच्छे निजी अस्पतालों में खर्चा इतना अधिक है कि वहां आम आदमी पहले तो जाता नहीं है और यदि चला गया तो वह उस खर्चे को सहन करने में सक्षम नहीं है। जैसे-जैसे संक्रमण का ग्राफ बढ़ेगा ऐसी परिस्थितियां और अधिक दिखाई देने लगेंगी। जो एक डरावना मंजर होगा।

हम हिम्मत न हारें, अवसाद में न जाएं, निराश न हों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आशावादी सोच बनाए रखें नियमित रूप से योग व्यायाम एवं खानपान की सहायता से स्वयं को स्वस्थ रखें तो कोरोना वायरस तो क्या कोई भी वायरस हमारा अधिक नुकसान नहीं कर पाएगा।

अतः मरीजों को टालने की प्रवृत्ति को हर हाल में रोकना होगा, लेकिन एक अच्छी खबर भी इस बीच आ रही है और वह यह है की कोरोना वायरस यानी कोविड-19 अब लगातार कम खतरनाक वायरस में तब्दील होता जाएगा। वह संक्रमित तो करेगा, लेकिन अच्छी वाली इम्यूनिटी वाले लोगों की जान लेने लायक नहीं बचेगा। अभी वर्तमान में ही भारत में रिकवरी रेट लगभग 58 प्रतिशत पार कर गया है और आने वाले समय में इसके 80 प्रतिशत को भी पार करने की प्रबल संभावना है। भले ही कोविड-19 फैले अस्पताल भरे हुए नजर आएं टीवी चैनलों पर आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखे कुछ स्थानों पर एडवांस में कमरे भरे हुए दिखाई दें या अधिक श्मशान घाट बनाए जाएं, लेकिन घबराइएगा नहीं। कोविड-19 भारत में बहुत अधिक जान नहीं ले पाएगा, लेकिन हां अगर हम अनलॉक को स्वच्छंदता बना लिया, नियमों की अनदेखी करनी शुरू कर दी, सावधानियां बरतनी बंद कर दी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और केवल सरकारों के भरोसे ही बैठ गए तो कोरोना का डंक खतरनाक हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आवश्यकता है कि हम हिम्मत न हारें, अवसाद में न जाएं, निराश न हों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आशावादी सोच बनाए रखें नियमित रूप से योग व्यायाम एवं खानपान की सहायता से स्वयं को स्वस्थ रखें तो कोरोना वायरस तो क्या कोई भी वायरस हमारा अधिक नुकसान नहीं कर पाएगा। इसी बीच वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता एवं अनुभवी डॉक्टर सब मिलकर कोरोना की नाक में नकेल कर ही लेंगे। तो आप रहिए सावधान सतर्क करिएगा पालन नियमों का न रहें लापरवाह तो निश्चित ही सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ भी।

क्या है कोरोना

कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है। यह इंसान को काफी आसानी से संक्रमित कर सकता है। यह एक तरह का आरएनए वायरस है, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद लगातार फैलता है। इसके संक्रमण से सामान्य सर्दी-जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ और न्यूमोनिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह मनुष्यों के साथ मवेशियों, सूअरों, मुर्गियों, कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है।

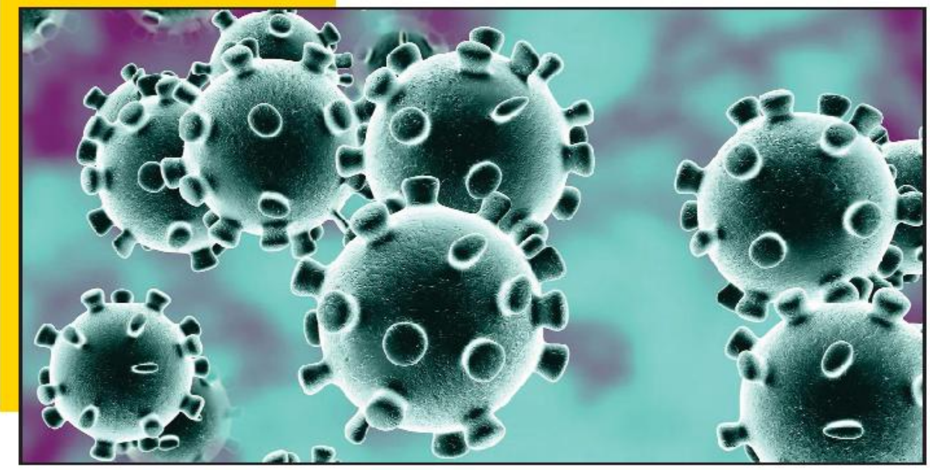

कोरोना का संक्रमण अधिकांश मामलों में खांसी, छींक, संक्रमित चीजों को छूने आदि से फैलता है। यह संक्रमण लार, चुंबन या फिर बर्तन शेयर करने से भी हो सकता है। यह संक्रमण फेफड़ों को संक्रमित करता है, इसलिए खांसते वक्त मुंह से निकले वाली बूंदें सामने मौजूद व्यक्ति को संक्रमित कर सकती हैं।

ऐसे बचें कोरोना वायरस से

- अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन या हैंड वाश से धोएं। अगर साबुन ना हो तो सेनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।
- छींक या खांसी आने पर अपनी नाक या मुंह को टिशू से ढकें और फिर उसे डस्टबिन में फेंक दें।
- गंदे हाथों से अपनी नाक और मुंह को न छुएं और न ही गंदे हाथों से कुछ खाएं।
- बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें। उनके बर्तन का इस्तेमाल ना करें और उन्हें छुएं भी नहीं। इससे मरीज़ और आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे।
- घर को साफ रखें और बाहर से आने वाली चीज़ों को भी साफ करके ही घर में लाएं।

कोविड-19 में साबुन की उपयोगिता

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ माह पूर्व कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से ही इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को लगातार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। साबुन इसके लिए सबसे सस्ता, सुलभ और सुरक्षित उपाय माना गया है। शोधकर्ताओं का भी एक स्वर में यही कहना है कि कोरोना के कहर से बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें।

कोरोना
प्राकृतिक वायरस नहीं

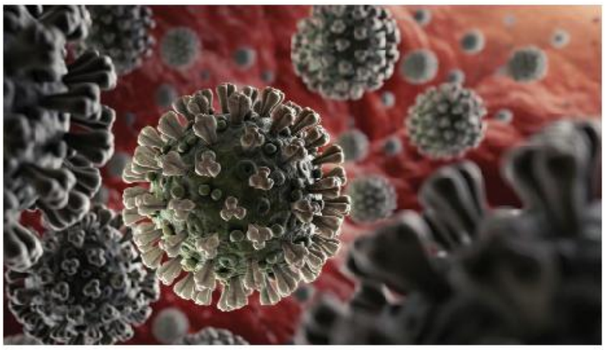

जापान के मेडिसीन के प्रोफेसर डॉ. तास्कू होन्जो ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस कोई स्वाभाविक रूप से फैला हुआ वायरस नहीं है। यह शुद्ध रूप से मानव निर्मित है, जो चीन के वुहान की प्रयोगशाला में बनाया गया है। डॉ. तास्कू होन्जो जो जापान के कीटो विश्वविद्यालय में इम्युनिलॉजी एवं जीनोमिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं और जिन्हें 2018 में इम्युनिलॉजी के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉ. होन्जो ने कहा मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वायरस पूर्णतः मानव निर्मित है और इसका चमगादड़ से कुछ भी लेना देना है ही नहीं! यह झूठ फैलाया जा रही है कि यह वायरस चमगादड़ों के माध्यम से आया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डॉ. तास्कू होन्जो ने बताया कि मैं स्वयं चीन के वुहान में स्थित वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में चार वर्षों तक काम कर रहा था और वहां के एक-एक वैज्ञानिक और टेक्नीशियन अच्छी तरह मेरे परिचित हैं। जब यह वायरस फैला तब मैंने वुहान प्रयोगशालाओं में कार्यरत अपने सभी वैज्ञानिक मित्रों में से एक-एक को फोन किया, लेकिन किसी का फोन भी चालू हालत में नहीं मिला। सबके फोन या तो बंद थे या पूरी तरह डेड थे। मेरे तीन महीने के प्रयास के बाद अब यह पता चल रहा है कि वुहान के ये सारे वैज्ञानिक और टेक्नीशियन अब न तो उस प्रयोगशाला में है और न ही इस दुनिया में। यह एक बहुत ही गंभीर बात है।

डॉ. तास्कू होन्जो

आखिर चीन ने ऐसा किया क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि चीन खुद अपनी आबादी को कम करना चाहता था, लेकिन ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि चीन को यह बर्दाश्त नहीं था कि अमेरिका विश्व की नंबर एक आर्थिक ताकत बनी रहे। चीन चाहता था कि वह किसी न किसी प्रकार से विश्व की पहली ताकत बन जाए इसके लिए चीन ने वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयास भी किए। वह संभव हो पाएगा कि नहीं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि डॉ. होन्जो के इस बयान ने पूरे विश्व में खलबली मचा दी है और कोरोना मानव निर्मित वायरस है इस पर जांच हो, इसकी मांग अब और ज्यादा पुख्ता होकर उभर गई है।

दुनिया भर में कोरोना का प्रभाव (आँकड़े दिनांक 10 जुलाई 2020 तक)

	विश्व में	भारत में	मध्यप्रदेश में
कुल संक्रमित	124.30लाख	7.98लाख	16657
कुल मृत्यु	5.58लाख	21656	638
स्वस्थ हुए	72.52लाख	4.97लाख	12481

शहर	कुल संक्रमित	कुल मौतें
इंदौर	5176	261
भोपाल	3677	117
उज्जैन	880	71
खंडवा	383	17
रतलाम	210	6
खरगोन	344	15

मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर
माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान
को हार्दिक शुभकामनाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
की हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसान भाइयों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड | कृषि यंत्र के लिए ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन) | मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण | खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्रीमती भारती शेखावत
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से :
श्री राजेंद्र शर्मा (शा.प्र. राजवाड़ा), श्री गिरीश देवासकर (शा.प्र. महिला शाखा), श्री नंदराम वर्मा (शा.प्र. बगड़ी)

आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. नौगाँव, जि.धार **श्री पन्नालाल सिसौदिया** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. बिलौदा, जि.धार **श्री महेंद्रसिंह ठाकुर** (समिति प्रबंधक)
आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. तोरनोद, जि.धार **श्री जितेंद्र यादव** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. बगड़ी, जि.धार **श्री नंदराम वर्मा** (समिति प्रबंधक)
आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. मोहनपुर, जि.धार **श्री अंतरसिंह** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. नालछा, जि.धार **श्री रामगोपाल वर्मा** (समिति प्रबंधक)
आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. सलकनपुर, जि.धार **श्री दीपक सिसौदिया** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. छोटा जामन्या, जि.धार **श्री कनिराम मंडलोई** (समिति प्रबंधक)
आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. तीसगाँव, जि.धार **श्री सुरेश ठाकुर** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. चंदरपुरा, जि.धार **श्री जितेंद्र पटेल** (समिति प्रबंधक)
आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. उमरियाबड़ा, जि.धार **श्री श्याम परमार** (समिति प्रबंधक)	आ.जा. सेवा सह. संस्था मर्या. बाछनपुर, जि.धार **श्री अरुण शर्मा** (समिति प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

सहकारिता से जलवायु परिवर्तन

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस वर्ष 4 जुलाई को पड़ रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र के पूरक लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन को प्रकाश में लाना है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय 'जलवायु परिवर्तन' है। थीम की घोषणा करते हुए आई.सी.ए. के अध्यक्ष एरियल गुआर्को ने कहा, हमें वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना होगा कि सामाजिक समावेश और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ अर्थव्यवस्था विकसित करना संभव है। हमारा घर खतरे में है। उत्पादन और उपभोग के ऐसे तरीके हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं है। हमें अब अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ काम करना चाहिए।

विश्व भर के सहकारी समुदाय को जलवायु परिवर्तन से जुड़े हर कार्य को जारी रखने पर जोर देने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यह विकट स्थिति जीवन और आजीविका को जोखिम में डाल रही है और लोगों तथा पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों को बाधित कर रही है। हम जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 1990 की अपेक्षा आज 50 प्रतिशत से अधिक है, और ग्लोबल वार्मिंग हमारे जलवायु प्रणाली में लंबे समय से स्थायी परिवर्तन का कारण बन रही है जो अपरिवर्तनीय परिणामों की धमकी दे रही है।

दुनिया भर में सहकारी समितियां नेतृत्व प्रदान करने और इस वैश्विक मुद्दे का मुकाबला करने में अपने सहकारी मूल्यों को साझा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं। को-ऑपरेटर्स कम्युनिकेशंस गाइड जल्द ही सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जलवायु परिवर्तन पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने के महत्व का वर्णन करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने में मदद मिल सके।

जैसा कि हमने पिछले साल किया था, डॉट कॉप के साथ मिलकर हम 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के इंटरेक्टिव मानचित्र को लॉंच कर रहे हैं ताकि यह बताया जा सके कि दुनिया भर की सहकारी समितियां जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कैसे कदम उठा रही हैं और उनकी सफलताओं का जश्न मना रही हैं। पिछले साल हमने दुनिया भर के लगभग 40 देशों में 130 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए।

2020 इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे थीम को क्लाइमेट एक्शन पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) 13 का समर्थन करने के लिए चुना गया था। यह आयोजन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सहकारी आंदोलन इस महत्वपूर्ण अवसर का उपयोग परिवर्तन के वैश्विक अभिनेता के रूप में एक स्टैंड लेने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करने के लिए कर सकता है। यह सामूहिक प्रयास जलवायु एजेंडे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है और सभी समुदायों के लिए उचित, स्वच्छ और न्यायोचित मार्ग प्राप्त कर सकता है, जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा।

नए अवसरों का सृजन करती सहकारिता

» डॉ. राधेश्याम द्विवेदी

इतिहास के पन्ने पलटने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 1923 से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा हर वर्ष जुलाई माह के पहले शनिवार को विश्व सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर नियमतः अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एलायंस (आईसीए) अपने सदस्यों से अपील करता है कि वे सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दें और घटनाओं के आयोजन, पैरवी में हिस्सा लेकर, आदि द्वारा अपने अभियान आदि में राष्ट्रीय और स्थानीय सहकारी पहल का समर्थन करें। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता आंदोलन और सरकार सहित अन्य अभिनेताओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईसीए और अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठन संदेश जारी करता है। वर्ष 1923 में जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाये गये पहले विश्व सहकारिता दिवस को सहकारिता को सर्वमान्य पहचान देने का उद्देश्य रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी जे डी सी. गोदर्थ ने सहकारी आन्दोलन के विकास में बाधा बने कारणों की तरफ ध्यान आकृष्ट कर यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक देश में प्रचार -प्रसार दिवस या प्रचार-प्रसार संध्या समारोह आयोजित कर विश्व भर में यह बताया जाये कि सहकारिता आन्दोलन क्या कर रहा है। यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया और वर्ष 1922 में सम्पन्न कार्यकारिणी की बैठक में जुलाई के प्रथम शनिवार को विश्व सहकारिता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तभी से हर वर्ष विश्व सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। 1923 में जब प्रथम बार इसका आयोजन हुआ तब इसमें सहकारिता का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक दक्षता, शांति और समानता की चर्चा प्रमुखता से हुई। विश्व सहकारी आंदोलन के शीर्ष संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी परिसंघ की स्थापना 1885 में हुई।

सन् 1995 में सहकारिता के विश्वमान्य सिध्दान्तों को नये स्वरूप में मान्यता दी गई है। जिसके तहत सिध्दान्तों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सहकारिता से प्राप्त होने वाली समृध्दि से किस प्रकार संतुष्टि प्राप्त होती है, इसका एहसास सभी को कराने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस दिवस पर सहकारिता के महान लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप मिलजुल कर संपदा सृजन और समान वितरण के लक्ष्य को लेकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया जाता है। सहकारी संस्थान आर्थिक उत्थान और विश्व शांति का संदेश भी इस दिवस पर देते हैं।

सहकारी आन्दोलन ने समाज के उपेक्षित वर्ग को संगठनात्मक शक्ति उपलब्ध कराई है। सहकारिता के इस आन्दोलन ने अभावग्रस्तता से लड़ने, सामाजिक एकीकरण और रोजगार के अवसर सहज मुहैया कराने का साहस किया है। देश में सहकारिता के क्षेत्र में कुछ संस्थाओं ने अपने कार्य के तरीकों से विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सहकारिता की जन्मस्थली भारत ही है। सहकारिता के सभी गुण व संस्कृति यहां की रगरग मे रची बसी है। हमारे पूर्वजों ने आपस में मिलकर संगठन बनाकर अपने अभीष्ट को प्राप्त किया था। सहकारिता संगठित शक्ति, सृजन दृष्टि एवं सर्वांगीण उन्नति का परिणाम है। सहकारिता की यह परंपरा अच्छी है कि इसमें चाहे सहकारी संस्थाओं के सदस्य हो या पदाधिकारी हो अथवा कर्मचारी या अधिकारी सभी सहकारी कार्यकर्ता कहलाते है। सहकारी आन्दोलन को दशा और दिशा बदलने के लिए सदस्यों को शक्ति

सम्पन्न बनाना आवश्यक है। ग्रामीण कृषकों को सहकारिता के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। कृषि ऋण एवं उर्वरक वितरण में व्यावसायिक बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से आगे रहकर ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना है ताकि सहकारिता से जुडा हर व्यक्तित गौरवान्वित हो सके। सहकारिता के विकास के लिए आपसी समन्वय एवं टीमभावना से काम करने की आवश्यकता है।

प्रदेश में सहकारिता सभी क्षेत्रों तथा नवीन दिशाओं में तेजी के साथ आगे बढे, इसका लाभ सभी तबके को समान रूप से प्राप्त हो। संस्थाओं में प्रबंध की कुशलता बढाई जाने तथा प्रबंध का पूर्ण व्यावसायीकरण हो। सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों में पूर्ण पारदर्शिता दृष्टिगोचर हो। संस्थाएँ आर्थिक रूप से सुदृढ एवं कार्यकुशल हो। सभी संस्थाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। सदस्य तथा प्रबंध शिक्षण की पूर्ण व्यवस्था की जाए। कृषि साख संस्थाएं कम से कम ब्याज दर पर पूर्ण ऋण कृषको को प्रदान करें। शासन ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की है इसका पालन सुनिश्चित किया जाय। सहकारिता के आर्थिक अपराधों तथा जिला स्तर पर आंतरिक पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है। शासकीय स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों में शीघ्र निर्णय लिए जाए। प्रो. वैद्यनाथन कमेटी की सिफारिशों से केन्द्रीय जिला सहकारी संस्थाएं जो धारा 11 में है वे उभर जाएँगी। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तथा कार्यकुशलता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों को सुदृढ बनाया जा सकेगा तथा उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। संस्थाओं की आर्थिक सक्षमता पर भी अच्छा प्रभाव पडेगा। संस्थाओं में आधुनिकीकरण होगा और मानीटियरिंग पद्धति में सुधार आयगा। इससे प्रदेश की सहकारिता सशक्त होगी।

सहकारिता एक शाश्वत आर्थिक पद्धति है। इन्ही शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के अनुपालन के फलस्वरूप सहकारिता आज के प्रतियोगिता के युग में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अन्य प्रमुख गुण सहकारी पद्धति का है। सभी आर्थिक पद्धतियां पूँजीवाद अथवा समाजवाद में अपनी स्थिति और उपस्थिति को कायम रखने की शक्ति। इसी शक्ति में सहकारिता को गतिशील और सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण आर्थिक पध्दति बनाया है। परिणामतः विश्व के हर महाद्वीप में लगभग हर देश में सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में लगी हुई है। चाहे वह भारत और चीन जैसे विशाल देश हो अथवा सिंगापुर, फिजी जैसे छोटे देश, हर जगह सहकारी संगठन विद्यमान है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को संगठित कर नए अवसरों का सृजन कर रहे है। आर्थिक उदारीकरण के युग में सहकारिता उच्चकोटि की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं व्यावसायिक प्रबंध व्यवस्था से शिखर स्थान प्राप्त कर सकती है और आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता प्रदर्शित कर सकती है।

सदस्यता फॉर्म

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

नियमित अंकों सहित विशेषांक भी

सदस्यता शुल्क

480/-	850/-	9000/-
वार्षिक	द्विवार्षिक	आजीवन

नाम : ....

पिता : ....

पता : ....

....

....

पिनकोड : ....

फोन : ....

मोबाइल : ....

ई-मेल : ....

सम्पर्क करें

हरियाली के रास्ते

306/ए-ब्लॉक, शहनाई-II रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 9752558186

सदस्यता शुल्क जमा करने हेतु बैंक अकाउंट विवरण

» खाता नाम : हरियाली के रास्ते
» बैंक : भारतीय स्टेट बैंक » शाखा : गोयल नगर
» खाता संख्या : 31450697620 » SBIN0030412
» PAN Card No. AHGPT7845K

अनुरोध : सदस्यों से अनुरोध है कि सदस्यता प्राप्त करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें।

भारत में सहकारिता आंदोलन

मिल-जुलकर काम करने की प्रणाली को सहकारिता कहते हैं। जो कार्य एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, उसे सामूहिक रूप से करना अधिक लाभदायक होता है। स्वराज के प्रारंभिक काल में देश का आथिक विकास बहुत मंद गति से हो रहा था। उसे पूरा करने के लिए राष्ट्र के कर्णधारों ने आर्थिक नीति को समाजवादी रूप दिया। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को महत्त्व दिया गया है। छोटी-छोटी सहकारिता समितियों में सहकारिता के सफल होने पर उस पर जनता का विश्वास जमता है तथा जनता का भरपूर सहयोग भी मिल सकता है।

इसके लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र देहात है, जहाँ के लोग प्रायः गरीब होते हैं और अपने साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। वे छोटे-मोटे काम-धंधे कर सकते हैं, मगर पूँजी उनके पास नहीं होती है। अतः उन्हें ऋण दिलाने की व्यवस्था हो। उनके पास जमीन तो है, मगर वह छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी पड़ी है। अतः उसे सबकी भूमि बनाकर सहकारी खेती की जाए। इस प्रकार ग्रामीणों के साधनों द्वारा उत्पादन बढ़ाने और तैयार माल की बिक्री करने के लिए वहाँ सहकारी संगठनों की आवश्यकता है। सामान्य तथा सामूहिक प्रयत्नों में व्यक्ति में आस्था का अभाव रहता है, क्योंकि व्यक्तिगत कार्य के साथ व्यक्ति का अपनापन रहता है।

'अमूल' दुनिया का दूध के क्षेत्र में सबसे बड़ा सहकारी संगठन है।

समूह हित के लिए व्यक्ति के सेवा-भाव को जगाना कठिन होने पर भी समूह-भाव का संस्कार लाए बिना सहकारिता का कार्य सफल नहीं हो सकेगा। इसके लिए उन्हें सतत व्यावहारिक प्रेरणा मिलती रहती है। उनको उपज के संग्रह, उसकी बिक्री की व्यवस्था, कारीगरों की समितियों का गठन, उनके हितों की रक्षा आदि कार्यों में स्थानीय सहकारी समितियों के समर्थन-प्रवर्तन से ग्रामीणों में सहकारिता का भाव दृढ़ हो सकेगा। इस कार्य में सरकार स्वयं हिस्सेदार बनकर बैंकों, ऋण-समितियों, भूमि प्रबंधन बैंकों, उपज संग्रह के लिए गोदामों के निर्माण आदि के जरिए सहकारिता सिद्धांत को प्रयोग में लाने का प्रयत्न कर रही है। सहकारिता के अनेक लाभ हैं।

सम्मिलित प्रयास से बड़े-बड़े कार्य भी सरलता से पूरे किए जा सकते हैं; आय का वितरण किया जा सकता है। कम ब्याज में पूँजी आसानी से हासिल हो सकती है। लोगों में परस्पर विश्वास की वृद्धि होगी। बैर-विरोध, मुकदमेबाजी घटेगी। सेवाशील व्यक्तियों की पहचान और चुनाव का कार्य आसान होगा। सहकारिता की योजना को सफल बनाने के बीच की बाधाओं का निवारण आवश्यक है। सरकारी कार्यालयों के कागजात किसानों के लिए मुसीबत न बनें, साथ ही किसान जिस कार्य के लिए ऋण लेता है, वह और किसी मद में खर्च न करे तथा ऋण की अदायगी में असमर्थता न दिखाए। इन बातों पर सरकार का नियंत्रण रहे, तभी यह योजना लाभकारी रह पाएगी।

सहकारिता को अपनाकर ही भारत में दुग्ध-क्रांति को सफल बनाया जा सका। इसके लिए दुग्ध एकत्रित करने के लिए गाँव-स्तर पर सहकारी समितियाँ गठित की गईं। इससे किसानों और दुग्ध-उत्पादकों को भारी लाभ हुआ। इसमें बिचौलियों का कोई स्थान न रहा। जो सामूहिक लाभ होता है, उसे अंशधारियों में बाँट दिया जाता है। 'अमूल' दुनिया का दूध के क्षेत्र में सबसे बड़ा सहकारी संगठन है। इसके अलावा सहकारी कृषि उपज मंडी समितियों का गठन ब्लॉक स्तर तक कर दिया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज का पूरा-पूरा दाम मिल रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान
को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री मुकेश जैन
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री अनूप जैन
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी)
सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. खरगोन

बायोस्टेड इंडिया लि. के उत्कृष्ट उत्पाद
BIOSTADT
बायोज़ाइम®
जीव विज्ञान पर आधारित
पौधों के लिए सम्पूर्ण विकास वर्धक,
अधिकतम पैदावार एवं बेहतर
क्वालिटी के लिए
BIOZYME Vegetable GRANULES
BIOZYME GRANULES
बायोज़ाइम ग्रेन्यूल्स
BIOZYME SOYA + GRANULES
BIOZYME Vegetable
वितरक :
पटवारी एग्रो एजेन्सीज
17, विशाल टॉवर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, नवलखा, इंदौर (म.प्र.)
फोन : (ऑ.) 2403694, 2400412,
(बिजलपुर) 2321668, 2321918, (नि.) 2321723

सहकारिता को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारी नेता

इटली के एम.आर. मजीनी

इटली में श्रम सहकारिता का बीजारोपण किया तथा उसे अर्थव्यवस्था का वटवृक्ष बना दिया। उन्होंने सभी प्रकार के श्रमिकों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उन्हें समीप से देखा। इस सहकारिता जनक के मार्गदर्शन से वर्ष 1883 में सर्वप्रथम श्रम समिति रीना की ब्राशियान्टी द्वारा स्थापित की गई। इसमें 303 श्रमिकों ने सदस्यता ग्रहण की तथा ओसरिया की दलदली और मच्छरों से भरी भूमि को एक हरे-भरे विशाल नगर में परिवर्तित कर दिया। श्री मजीनी के प्रयास से इटली में सन् 1888 में गियोलिटी अधिनियम पारित हुआ। इससे श्रम सहकारिता को लोक कार्यों के लिए प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार मिला। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक सहकारिताएँ 700 हो गई। संस्थाओं को संघ बनाने की दिशा में विचार-विमर्श किया गया। 1909 के दूसरे अधिनियम में श्रम समितियों के संगठन स्थापित करने का प्रावधान किया गया। समितियों को 6 लाख लीरा तथा केंद्रीय संगठनों को 300 लाख लीरा के लोक कार्य मिलने लगे।

भारत के डॉ. एस.के. सक्सेना

उत्तरप्रदेश में जन्मे श्री डॉ. एस.के. सक्सेना का नाम विश्व की शीर्षस्थ सहकारी संस्था 'अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ जेनेवा' के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री की उपाधि सोशल स्टडीज संस्थान हेग से प्राप्त की थी। पीएचडी की उपाधि अर्थशास्त्र में जेमिन्टे विश्वविद्यालय से ली थी। श्री डॉ. सक्सेना को अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ का मुख्य कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया। आपने 13 वर्ष तक इस पद को सुशोभित किया। वे प्रथम भारतीय विद्वान थे जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया गया। आपका कार्यालय लंदन में था। बाद में इसे जेनेवा स्थानांतरित किया गया। आपने संभागीय कार्यालयों के विस्तार की योजना बनाई। वर्तमान में 4 कार्यालय सिंगापुर, केन्या, कोस्टारिका तथा बेल्जियम में कार्यरत है। वे अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ के क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली के 8 वर्ष तक संभागीय निर्देशक रहे। यद्यपि डॉ.सक्सेना ने कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी।

चीन के डॉ. सनयात सेन

डॉ. सनयात सेन ने चीन की दरिद्र जनता के बहुमुखी आर्थिक उत्थान के लिए एक नियोजित सहकारी अर्थव्यवस्था की कल्पना की तथा उसे राष्ट्रीय नीति स्वीकार किया। उन्होंने जनता को रोजगार प्रदान करने के लिए औद्योगिक सहकारिता का नारा बुलंद किया। डॉ. सेन के मार्गदर्शन में शंघाई के कुछ साहसियों ने अप्रैल 1938 में शंघाई प्रोत्साहन कमेटी का गठन किया। चीन की सहकारिता अधिनियम बनाने में श्री सेन की मुख्य भूमिका थी। वर्ष 1942 में चुंगकिंग सरकार ने एक केंद्रीय मुख्यालय स्थापित कर सहकारी आंदोलन को गति प्रदान की। प्रांतों में सहकारिता हेतु डिपो गठित किए गए। संघीय ट्रेजरी वित्त उपलब्ध कराती है। डॉ. सेन ने सहकारिता को विकसित करने में शिक्षण एवं प्रशिक्षण को अभूतपूर्व स्थान दिया। कारण स्पष्ट है जागरुक तथा व्यावसायिक प्रबंध के दृष्टिकोण वाला नेतृत्व सहकारी उपक्रम की सफलता का सूत्र है।

जर्मनी के ए.एफ. रेफेसन

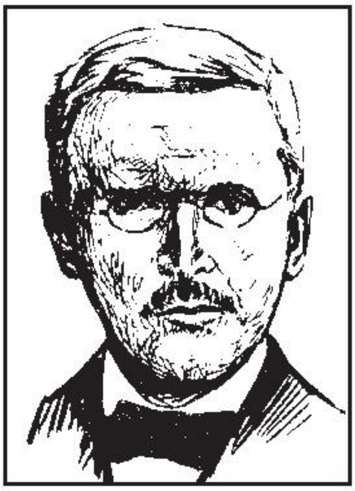

19वीं शताब्दी में यहक्षदियों के अत्याचारों के कारण जर्मनी के गाँवों में निर्धन कृषकों की हालत अत्यंत दयनीय थी। पूरा देश अत्यधिक ब्याज लेने वालों का नर्क बन गया था। ऐसे माहौल में रेफिजन वेस्ट वाल्ड नामक जिले में श्री ए.एफ. रेफसन को मेयर बनाया गया। उन्होंने मेयर बनते ही सहकारिता का दामन थामा। उसने ग्रामीण जनता को संदेश दिया 'प्रत्येक सब के लिए, सब प्रत्येक के लिए'। जर्मनी का प्रथम सहकारी अधिनियम सन् 1889 में पारित हुआ जो रेफसन की भावनाओं के अनुरूप था। इनको सहकारी संस्थाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण को नियोजित कर उनके परिणामों की समीक्षा कर प्रत्येक को अपने दायित्वों एवं अधिकारों के प्रति सजग किया।

राबर्ट ओवन

सहकारिता के अग्रदूत राबर्ट ओवन का जन्म 14 मई 1771 को न्यूटन नगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। सहयोगी ग्रामों की योजना जिसमे 500 से लेकर 3000 तक सदस्य, 1500 एकड़ भूमि पर एक सामुदायिक समाज के रूप में रहेंगे, विश्व में विख्यात है। राबर्ट ने कहा था 'आपको स्वयं का व्यापारी तथा स्वयं का उत्पादक होना चाहिए जिससे आप स्वयं कम मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकें।' ओवन की सहकारिता का केंद्रबिंदु गरीब था।

जापान के टोयोहीको कागावा

जापान के सहकारिता आंदोलन के जनक श्री टोयोहीको कागावा का जन्म कोबे के एक संसदीय अधिकारी के घर हुआ था। उनका कार्यकाल 1888 से 1960 तक रहा। उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 70 पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने सहकारी साख संगठन जिन्हें 'को या मुजीया' कहते हैं प्रारंभ किया। इनकी स्थापना पारंपरिक सहायता के सिद्धांतों के अनुरूप की गई। आधुनिक पारस्परिक बैंकें उन्हीं का रूप है। श्री कागावा ने सहकारी सिद्धांतों को व्यावहारिक जामा पहनाया। श्री कागावा के कारण आज जापान में सहकारिता संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, जीवन तथा रहन-सहन की पद्धति बन गई है। कृषि सहकारिता के साथ ही उपभोक्ता, आवास, औद्योगिकी सहकारिता का भी खूब विकास हुआ है। 'इडाका' विश्व में कृषि सहकारिता का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। इसकी स्थापना

श्री कागावा ने की थी।

चीन के प्रोफेसर हेने

चीन की सहकारिता में साम्यवादी चीन के अधिष्ठाता श्री डॉ. सनयार हेने का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रो. हेने ने एक राष्ट्रीय सहकारी विकास की योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में सहकारी समितियाँ और सहकारी ब्यूरो स्थापित किए गए। लघु सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया। वर्ष 1938 में केंद्रीय सहकारी विद्यालय स्थापित किया। सभी सहकारी विचारक एवं दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान करते थे। प्रो. हेने ने चीन में ग्रामीण आपूर्ति एवं विपणन समितियों की स्थापना की। उनका विचार था कि कृषि उपज का विपणन यदि सही नहीं रहा तो कृषक प्रगति नहीं कर सकेगा। इन समितियों के बहुउद्देश्य तथा बहुकाय है। सदस्यता का विस्तार सहकारी नेता का स्वप्न था। सहकारिता को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास किए गए। नगरीय उपभोक्ता भंडारों की स्थापना भी की। सच्ची सहकारिता के इस समर्थक ने शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से आंदोलन का सही स्वरूप सबको समझाया। श्री हेने ने सामुहिक कृषि का श्री गणेश किया। समिति सक्षम हो इसका सदैव ध्यान रखा। 100 परिवार मिल-जुलकर खेती के समस्त कार्य करते थे। कृषि साधनों का स्वामित्व सामुहिक रखा। इस सहकारी नेता ने स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने पश्चात् विकास योजना का निर्माण किया। सहकारिता के विकास तथा संरक्षण हेतु जो भी आवश्यक नियम, उप नियम, उपविधियों तथा अधिनियम बने उनमें व्यावहारिकता का पुट रहे, इसका सदैव ध्यान रखा गया। सहकारिता की चेन गाँव से लेकर राजधानी तक बनने का सिद्धांत प्रतिपादित किया।

आयरलैंड के सर होरेस प्लंकेट

सर होरेस प्लंकेट का जन्म सन् 1854 में एक भूमिपति परिवार में हुआ था। इस सहकारी नेता ने उन सभी के आँसू पोंछे जो एक लंबे समय से दुःखी थे। इन्होंने उत्तम कृषि, उत्तम व्यापार और उत्तम जीवन का नारा दिया। इन्होंने अपने मित्र जे.सी. ग्रेके सहयोग से कृषि सहकारिता में कार्य प्रारंभ किया। एक सहकारी डेरी प्रारंभ की जिसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। छोटे-छोटे परिवार जिनके पास गाय हैं, उन्हें डेरी स्थापित करने को प्रेरित किया। वर्ष 1946 में डेरियों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई गई तथा उसको विधिपूर्वक क्रियान्वित किया। साख संस्थाओं के निर्माण में भी श्री प्लंकेट का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्थाएँ 3 मील के क्षेत्र में बचत ऋण का आधार, स्थानीय प्रजातांत्रिक प्रबंध, ऋण सीमित सदस्य अंशपूँजी कम, संबंध घनिष्ठ एवं भावना सहयोगी, इन संस्थाओं की अपनी विशेषता थी इन्होंने सभी तत्वों में व्यावहारिक पहलू को अपनाया। इस सहकारी नेता ने राष्ट्रीय सहकारी परिषद के निर्माण का विचार भी दिया, ऐसी परिषद वर्ष 1954 में गठित की गई थी। श्री प्लंकेट की अध्यक्षता में आयरिश कृषि संगठन समिति की स्थापना वर्ष 1894 में की गई थी। सहकारिता के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर इस विद्वान ने अपने विचार अनेक संगोष्ठियों में दिए। आयरलैंड का सहकारी आंदोलन आज भी उनका सम्मान करता है।

जर्मनी के हेर फान्ज सुल्जे

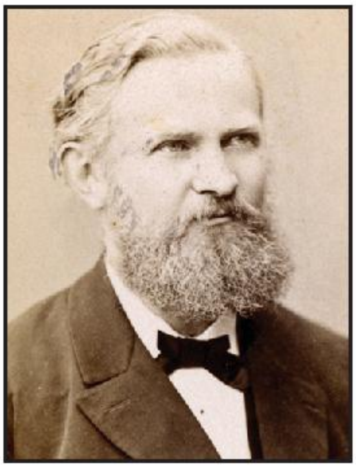

हेर फान्ज सुल्जे (1808-1883) डिलीन नामक कस्बा (जर्मनी) के मेयर थे तथा अकाल आयोग के अध्यक्ष। वे एक अच्छे वक्ता एवं प्रचारक थे। उन्होंने 'आर्थिक इंजिल' नाम की एक अत्यंत रोचक पुस्तक लिखी थी जिसने देश में तूफान ला दिया। श्री सुल्जे ने वर्ष 1949 में निर्धनों को रोटी प्रदान करने के लिए धर्मार्ध बेकरी स्थापित की। इसी वर्ष एक चर्मकार सहकारी समिति का निर्माण भी किया। वर्ष 1950 में प्रथम द्रव्यपूर्ति समिति की स्थापना कर जर्मनी को एक नई सौगात दी जिसने विश्व में तहलका मचा दिया। सुल्जे के विचारों पर आधारित शहरी साख सहकारी समितियाँ मध्यमवर्गय मजदूरों को सस्ती दर पर सदस्यों को उनकी ईमानदारी की गारंटी पर केवल 3-4 माह के लिए ऋण प्रदान करती थी जो उपयुक्त समय पर पुनर्भुगतान करते थे। उन्होंने साख सहकारिता में संघों की स्थापना की। श्री सुल्जे ने ग्रामीण साख सहकारिता का जो इतिहास लिखा उसके पन्नों को पढ़कर विश्व के राष्ट्रों ने कृषि साख सहकारिता की संरचना का सूत्रपात किया। सामाजिक समरेता एवं पारस्परिक सहयोग सहकारिता के मुख्य स्तंभ बने। सहकारिता के प्रति समर्पित इस धनाढ्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अपना नाम सहकारी इतिहास में अमर कर लिया। ●

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री पी.के. सिद्धार्थ
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

अन्तराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

श्री सुरेश सांवलेकर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री डी.के. राय
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री शैलेन्द्र शर्मा (शा.प्र. राहतगढ़)
श्री अजय चौधरी (शा.प्र. मालथौन)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. राहतगढ़, जि.सागर
श्री दिलीप कुमार गोस्वामी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मालकी सलैया, जि.सागर
श्री राजकुमार तिवारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. ऐरन मिर्जापुर, जि.सागर
श्री किशोर यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बरखेड़ी सड़क, जि.सागर
श्री अशोक दुबे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सेमराझिला, जि.सागर
श्री देवराज कुशवाह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. झिला, जि.सागर
श्री महेश चौबे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हिरनखेड़ा, जि.सागर
श्री नाथूराम आठिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मसुरयाई, जि.सागर
श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्याय (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. ठकरई, जि.सागर
श्री बलरामसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भैंसा, जि.सागर
श्री गजराजसिंह राजपूत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सीहोरा, जि.सागर
श्री देवराज लोधी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मालथौन, जि.सागर
श्री उपेन्द्र मिश्रा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सेमरालोधी, जि.सागर
श्री अश्वनी श्रीवास्तव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बीकोरकलां, जि.सागर
श्री अरुण वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रजवांस, जि.सागर
श्री अवध किशोर सेन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खटोराकलां, जि.सागर
श्री मनोहर तिवारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रोंडा, जि.सागर
श्री रमेश तिवारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बंगेला, जि.सागर
श्री सतेन्द्रसिंह राजपूत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हिरनछिपा, जि.सागर
श्री रामकुमार रिछारिया (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं

» अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरणविद्

मानव ने कभी यह सोचा ही नहीं कि अन्य जीव-जंतु, जो प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए थे, उनका भी संतुलन में योगदान है। आज भी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, तो शायद अन्य जीवों के कारण ही।

पिछले कुछ वर्षों में दुनिया कई तरह की खबरों से विचलित हुई है, इनमें सबसे बड़ा मसला पर्यावरण से जुड़ा रहा है। इस दौरान आर्थिकी और कुदरत से जुड़ी आपदाओं से भी हमारा वास्ता पड़ा, जिनको अंततः प्रकृति के अतिक्रमण से जोड़कर ही देखा गया। पिछले कुछ समय की घटनाओं का यदि विश्लेषण करें, तो अब नए मिजाज के साथ हर वर्ष तूफान आ रहे हैं, जो जमकर तबाही मचाते हैं। अभी अम्फान से हुई तबाही के निशान मिटे भी न थे कि निसर्ग तूफान का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले दो-तीन दशकों में हमने कई बीमारियों के नाम भी पहली बार सुने। इनमें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और अब कोरोना जैसे महारोग मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को न समझ पाने के कारण ही पनपे हैं। साफ है, हम प्रकृति को समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

दरअसल, हमने अपने जीवन-चक्र में कभी इस बात को महत्व ही नहीं दिया कि हर तरह की हलचल प्रकृति से जुड़ी होती है। पहले बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं दशक भर पर अपना बड़ा असर डालती थीं, लेकिन हाल-फिलहाल के वर्षों में तो मानो ये रोजाना की घटनाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि आज का समाज धीरे-धीरे इनसे न जूझ पाने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि अब होने वाले ये आक्रमण सर्वव्यापी और कहीं ज्यादा असरकारी हैं। हमने कभी भी उस पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं की, जिससे प्रकृति और पृथ्वी जुड़ी है। हमने एक ही तंत्र को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दिया, वह है आर्थिक तंत्र। इसी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने विज्ञान की हर पहल झोंक दी, ताकि आरामतलबी का हमारा जीवन बना रहे। इतना ही नहीं, इस दरम्यान पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने कब्जे में रखा।

पिछले दो-तीन दशकों से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जिस प्रजाति की बढ़ी है, वह मनुष्य ही है। पहले पारिस्थितिकी किसी भी प्रजाति की संख्या तय करती थी, लेकिन जब से मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं, दुनिया में उसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई है। अदृश्य विषाणु और कीटाणु की बात यहां इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे हमेशा गौण स्थिति में रहे हैं और किसी छेड़छाड़ के बाद अपनी संख्या का प्रदर्शन कर पाते हैं। मनुष्य की अपने लिए जुटाने की भावना और अन्य जीवों को न समझने की मूर्खता का ही नतीजा है कि आज हम एक बड़े और अनोखे संकट में फंसे हुए हैं।

19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक हमने करीब 41 फीसदी उभयचर प्रजातियों को गंवा दिया। इतना ही नहीं,

समुद्री जीवों को भी खतरे में डाल दिया। इसके अलावा, दुनिया की 10 फीसदी कीट प्रजातियां अब हमारे बीच नहीं हैं। हमने समुद्र से भी 33 फीसदी कोरल रीफ को इस दुनिया से दूर कर दिया। इसी तरह, हमने करीब 90 फीसदी फसलों की प्रजातियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी से आज तक नौ फीसदी पालतू जानवरों की प्रजातियां भी अब हमारे साथ नहीं हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, हम सभी तरह की करीब 80 लाख प्रजातियों को खो चुके हैं और लगभग 10 लाख खत्म होने के कगार पर हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह हमने अपनी चारों तरफ प्रकृति के अन्य जीवों को दुनिया से विदा कर दिया है। ऐसा लगता है, हम अपनी बनाई मुसीबतों के साथ दुनिया में अकेले रह गए हैं।

समुद्र का हाल भी हमने बुरा कर दिया है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार माना जाता है कि समुद्र कार्बन उत्सर्जन का 60 फीसदी हिस्सा अवशोषित करते हैं, पर कार्बन उत्सर्जन के लगातार बढ़ने के कारण आज वहां भी 400 डेड जोन बन चुके हैं, मतलब अब इनमें जीवन नहीं दिखाई देते। वेटलैंड, यानी दलदली भूमि का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में हमने दुनिया की 15 फीसदी दलदली भूमि गंवा दी है। औद्योगिक क्रांति के बाद वन भी 68 फीसदी घट गए हैं और वर्ष 1992 से 2000 के बीच लाखों हेक्टेयर वन को अपनी जरूरतों के चलते हमने स्वाहा कर दिया है। इसके बदले में वन लगाने की हमारी पहल लगभग शून्य के बराबर है।

असल में, मानव ने कभी यह सोचा ही नहीं कि अन्य जीव-जंतु, जो प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए थे, उनका भी संतुलन में योगदान है। आज भी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है, तो शायद अन्य जीवों के कारण ही। आज कोरोना की महामारी ने सबको यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। हम दरअसल, उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए थे, इसीलिए हम आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, जहां इसी प्रकृति का एक अंश अदृश्य रूप में हमारे बीच में आया और हमें यह सबक सिखा गया कि अन्य जीव भी दृश्य या अदृश्य होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रकृति के संदेश को समझ लें और यह स्वीकार कर लें कि पृथ्वी मात्र मनुष्य की नहीं, बल्कि सबकी है। 'सबकी बात और सबका साथ' नारा अपनाने की जरूरत है। यह नारा सिर्फ मनुष्य और उसके विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उन तमाम जीवों से जोड़कर देखे जाने की पहल करनी होगी, जिन्हें प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए। यह सब करने के बाद ही हम शायद इस पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकेंगे और प्रकृति के कहर से स्वयं को बचा पाएंगे।

अब नए दौर में मध्यप्रदेश के किसान

कोरोना महामारी के संकटकाल ने मध्यप्रदेश में किसानों को एक ऐसी सौगात दे दी है, सामान्य दिनों में जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोरोना संकट के दौर में किसानों को आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ही झटके में मंडी अधिनियम में संशोधन करके किसानों को एक तरह से ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़ने का करिश्मा कर दिखाया। आढ़त का काम कर रहे व्यापारियों को अगर लायसेंस राज से मुक्ति मिली है तो किसानों के लिए भी यह एक तरह से आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बनाने का मौका कहा जा सकता है। कोरोना के इस संकट काल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। देश में भी खेती और किसान आर्थिक विमर्श के केन्द्र में हैं। केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने कृषि जिंसों की मार्केटिंग के लिए राज्य सरकारों को एक माडल एक्ट सौंप रखा है। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि पूरे देश में कृषि जिंसों के लिए बाजार की एक जैसी व्यवस्था हो जाए ताकि किसानों को अपना उत्पादन बेचने के बेहतर विकल्प मिल सकें। राज्य की पिछली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था। श्री चौहान को जब चौथी बार सरकार चलाने का मौका मिला है तो आपदा के इस दौर में उन्होंने किसानों के हित में मंडी एक्ट में संशोधन के साथ एक बड़ा किसान हितेषी कदम उठा लिया। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने किसानों के हित में मण्डी एक्ट में संशोधन किया गया है।

इस संशोधन का सीधा फायदा किसान को होगा। अब उसे अपने उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके लिए उसे अब मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं होगी। मंडियों में किसानों को लंबे इंतजार के साथ अपनी उपज की गुणवत्ता को लेकर कई परेशानियों से दो-चार होना पड़ता था। मंडी अधिनियम में संशोधन के बाद अब किसान घर बैठ कर भी अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेगा। जाहिर है कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षा के जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं, उसमें किसान की परेशानी कई गुना बढ़ना तय था। सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन से पहले भी किसानों के हित में कुछ कदम उठाए थे लेकिन अब मंडी अधिनियम में जरूरी बदलावों के बाद किसान के लिए अपनी फसल बेचना पहले से ज्यादा आसान और फायदे का सौदा साबित होगा। मंडी में जाकर समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का विकल्प किसान के पास जस का तस रहेगा। नई वैकल्पिक व्यवस्था बन जाने के बाद कृषि जिंसों के व्यापार में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। लायसेंसी व्यापारी अब किसान के घर या खेत पर जाकर ही उसकी फसल खरीद सकेगा। एक ही लायसेंस से व्यापारी प्रदेश में कहीं भी जाकर यह खरीददारी कर सकेगा। इससे बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होगी। मसलन भोपाल के एक

व्यापारी को यदि पिपरिया जाकर अरहर दाल खरीदना होती थी तो उसे वहां क लायसेंसी व्यापारी के माध्यम से खरीददारी करना होती थी। अब यह बाध्यता खत्म होगी तो इसका सीधा फायदा किसान के अलावा उपभोक्ता को भी मिलेगा।

सरकार ने ई-टेंडरिंग का भी इंतजाम किया है। इसके तहत पूरे देश की मंडियों के दाम किसान को मिल जाएंगे। वो देश की किसी भी मंडी में, जहां उसे दाम ज्यादा मिल रहे हों, अपनी फसल का सौदा कर सकेगा। फल और सब्जियों को पहले ही प्रदेश में मंडी अधिनियम से छूट हासिल है। इसके अलावा मंडी शुल्क भी केवल एक बार की खरीदी बिक्री पर देना होता है। उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मंडियां भी किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम था। पर अब समय के हिसाब से जरूरतें बदल रही हैं। इसके अलावा मंडियों के राजनीतिकरण के कारण मंडियां किसानों के लिए एक कुचक्र की तरह हो गई हैं, जिसमें किसान दबा, पीटा और लूटा नजर आ रहा था। वैसे भी जब दुनिया भर में मुक्त बाजार की अवधारणा फल फूल रही है तो किसानों को मंडियों के दायरे में बांधने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा, मंडी अधिनियम में संशोधन, किसान को मुक्त व्यापार से जोड़ने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। व्यवस्था में इस बदलाव का फायदा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को समान रूप से मिलने के आसार हैं। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत पर आम दस या बीस रूपए किलो में एक व्यापारी को बेचता है लेकिन उपभोक्ता तक जाते-जाते इस आम की कीमत अस्सी या सौ रूपए किलो हो जाती है। नई व्यवस्था में किसानों से मंडी के बाहर उसके गांव से ही फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता या फिर आखिरी उपयोगकर्ता सीधे किसान की उपज खरीद सकेगा। इसका एक मतलब यह होगा कि किसान अब अपने उत्पादन का व्यापारी भी खुद ही हो जाएगा।

मंडी अधिनियम में बदलाव के बाद अब गोदामों, साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी माना जाएगा। मंडी समितियों का इन प्रायवेट मंडियों के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि किसान के सामने भंडारण की जो समस्या हर फसल के सीजन में सामने खड़ी होती है, उसका समाधान एक तरह की गुंजाईश बनेंगी। अभी भंडारण की समस्या के कारण किसान अपनी उपज को लेकर हर समय एक तरह से आशंकाओं से ही घिरा रहता है। अधिनियम में संशोधन के बाद अब कम से कम ऐसा तो नहीं ही होगा कि उपज ज्यादा हो जाए , दाम गिर जाएं और किसान को उसे खेतों मे ही नष्ट करना पड़े। कोरोना आपदा के इस दौर में भी ऐसी खबरें हमें मिल ही रही हैं कि किसान की फल-सब्जियां खेतों में ही सड़ रही है। इसके अलावा भी सामान्य दिनों में इस तरह की खबरें मिलती हैं कि किसान को अपनी फसल मंडी में ले जाना महंगा पड़ रहा है इसलिए उसने फसल को नष्ट करना ही बेहतर समझा। किसान की यह पीड़ा अब कम होने के आसार हैं। अब किसान से फूड प्रोसेसर सीधे उसकी फसल आसानी से खरीद सकेंगे। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी प्रदेश में बढ़ावा मिलता दिखेगा।

भोपाल में ही सूरज नगर में रहने वाले किसान गौरेलाल कहते हैं कि सरकार के इन फैसलों में यह साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को न सिर्फ किसानों की चिंता है बल्कि एक किसान परिवार से होने के कारण किसानों की इन तकलीफों को वे बेहतर तरीके से जानते हैं। किसानों के हित में उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत किया है। जीरो ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के अलावा ब्याज पर सब्सिडी का मामला हो या फिर किसानों के हित में भावांतर योजना जैसे कदम। मुझे लगता है कि एक किसान पुत्र होने के कारण किसानों की वास्तविक तकलीफों को श्री चौहान बेहतर तरीके से समझते हैं। सरकार के इस कदम ने किसानों के लिए आर्थिक मंदी के इस दौर में एक नया रास्ता खोल दिया है। किसान के लिए आज बाजार बड़ा और व्यापक होता दिख रहा है।

सरकार के फैसलों में यह साफ झलकता है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को न सिर्फ किसानों की चिंता है बल्कि एक किसान परिवार से होने के कारण किसानों की इन तकलीफों को वे बेहतर तरीके से जानते हैं। सरकार के इस कदम ने किसानों के लिए आर्थिक मंदी के इस दौर में एक नया रास्ता खोल दिया है। किसान के लिए आज बाजार बड़ा और व्यापक होता दिख रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण ● खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड ● कृषि यंत्र के लिए ऋण ● दुग्ध डेयरी योजना

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ

सौजन्य से

श्री अशोक मंडलोई (शा.प्र. सूलगाँव)
श्री हरिशंकर (पर्य. सूलगाँव)
श्री विजय अवास्या (शा.प्र. किल्लोद)
श्री श्रीराम राजपूत (पर्य. किल्लोद)
श्री मनीष झारिया (शा.प्र. सिंगोट)
श्री हेमंत जैन/श्री फतेहसिंह चौहान (पर्य. सिंगोट)
श्री देवराम रूपाले (शा.प्र. बोरगाँव बुजुर्ग)
श्री रामदास पटेल (पर्य. बोरगाँव बुजुर्ग)

श्री जगदीश कन्नौज (बैंक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सह.)

श्री के. पाटनकर (उपायुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. हरसोला (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

श्री गजेन्द्र अत्रे (वित्त प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. घोघलगाँव, जि. खंडवा श्री हरिशंकर (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. पिपलानी, जि. खंडवा** श्री श्रीराम राजपूत (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. रामपुरा, जि. खंडवा** श्री हेमंत जैन (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सूलगाँव, जि. खंडवा श्री हरिशंकर (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बिल्लोद, जि. खंडवा** श्री शंकरलाल राजपूत (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. पाडल्या, जि. खंडवा** श्री फतेहसिंह चौहान (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. गौस, जि. खंडवा श्री चंदू जायसवाल (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. मालूद, जि. खंडवा** श्री मिथिल कुमार सोनी (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. गांधवा, जि. खंडवा** श्री संदीप पाटीदार (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. गोगाँवा, जि. खंडवा श्री सुभाष परमार (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. गंभीर, जि. खंडवा** श्री श्रीराम राजपूत (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. खिड़गाँव, जि. खंडवा** श्री हेमंत जैन (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. किल्लोद, जि. खंडवा श्री महेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. सिंगोट, जि. खंडवा** श्री प्रकाश यादव (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरगाँव बुजुर्ग, जि. खंडवा** श्री रामदास पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. खुदिया, जि. खंडवा श्री दिनेश मार्कण्डेय (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. भगवानपुरा, जि. खंडवा** श्री विजय ओंकार (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. रुस्तमपुर, जि. खंडवा** श्री राधेश्याम दशोरे (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोमगाँवखुर्द, जि. खंडवा श्री श्रीराम राजपूत (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. बलवाड़ा, जि. खंडवा** श्री फतेहसिंह चौहान (प्रबंधक)	**सेवा सहकारी संस्था मर्या. कोहदड़, जि. खंडवा** श्री रामदास पटेल (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

किसानों के लिए सामयिक सलाह

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को मृदा एवं जल संरक्षण के संबंध में सामयिक सलाह दी गई है। कृषकों से कहा गया है कि इस समय मृदा जल प्रबंधन हेतु जल निकास की प्रभावी व्यवस्था अवश्य करें, जिन खेतों में जल भराव होता है वहां पर सोयाबीन एवं मक्का दोनों ही फसलें लाभकारी नहीं है।

कृषि

■ गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ावें एवं नत्रजन की अंतिम मात्रा की पूर्ति करें। मानसून के पश्चात् गन्ने में नत्रजन की पूर्ति पायरिला कीट के प्रकोप को बढ़ाता है अतः मानसून पश्चात् गन्ने में नत्रजन न देवें।

■ खरीफ में प्रक्षेत्र की कार्ययोजना बनाते समय सोयाबीन, मक्का, ज्वार, धान के साथ-साथ कोदो, कुटकी आदि फसलों को भूमि के अनुसार समुचित स्थान देवें। सिर्फ सोयाबीन पर या सोयाबीन एवं मक्का पर पूर्ण निर्भरता कृषि के जोखिम को बढ़ाता है।

■ प्रमुख फसल की कम से कम दो प्रजातियों का चयन करें।

■ संकर बीज प्रतिवर्ष नया ही क्रय कर उपयोग करें। विगत वर्ष में संकर बीज से उत्पादित फसल से बीज न लेवें। ऐसा करने पर उत्पादन कम आवेगा।

■ खरीफ की बुवाई 3-5 इंच वर्षा हो जाने के बाद करें। मक्का, ज्वार एवं धान की शुष्क बोनी की जा सकती है परंतु अपर्याप्त नमी की अवस्था में कोई भी बुवाई या बानी ना करें।

■ पोषक तत्वों के प्रबंधन में सोयाबीन फसल में नत्रजन, स्फूर, पोटाश के साथ गंधक और अनाज वाली फसलें मक्का, ज्वार धान में प्रमुख तत्वों के साथ जस्ता का प्रयोग अवश्य करें। पोटाश, गंधक एवं जस्ता कीट एवं व्याधि के प्रकोप को कम करते हैं एवं फसल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

■ जैव उर्वरकों में राइजोबियम कृचर दलहनी फसलों के लिए, अजोटोबेक्टर अनाज वाली फसलों के लिए, पी.एस.बी. कृचर और के.एस.बी. कृचर सभी फसलों में प्रयोग कर रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को 50 प्रतिशत तक कम करें। ये जैव उर्वरक न सिर्फ लागत को कम करते हैं बल्कि भूमि की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा को सुधारते हैं।

■ धान की नर्सरी की बुवाई कर दें, श्री पद्धति में उपयुक्त उम्र की पौध प्राप्त करने हेतु रोपणी को अलग-अलग दो तिथियों में एक सप्ताह के अंतराल पर लगावें जिससे कि श्री पद्धति हेतु निर्धारित आयु 10-14 दिन की पौध उपलब्ध हो सकें। 14 दिन से अधिक उम्र की पौध इस पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है।

पौध संरक्षण

■ खरीफ फसलों को बोने के पूर्व बीजोपचार अनिवार्य रूप से करें। सोयाबीन एवं अन्य दलहन एवं तिलहन हेतु बीजोपचार थायोफिनेट मिथाइल . पायरोक्लस्ट्रोबिन (झेलोरा या अन्य) 2 मि.ली. .8 मि.ली. पानी/कि.ग्रा बीज एवं इमीडाक्लोप्रिड पॉवडर 2 ग्राम/किलो बीज की दर से उपचारित करें। बीजोपचार क्रमशः सर्वप्रथम कवकनाशी तत्पश्चात् कीटनाशी एवं अंत में जैव उर्वरक से करें।

■ खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन में बहुतायत से प्रति वर्ष आने वाला जड़ सड़न, तना सड़न रोग के प्रबंधन हेतु

बोनी के पूर्व या बोनी करते समय ट्राइकोडर्मा कल्चर 1 ली./एकड़ पर्याप्त नमी की अवस्था में भूमि में मिलावें।

■ नर्सरी में पाद गलन रोग के प्रबंधन हेतु रोपणी लगाते समय बीजों को कतार में बोवें और एक सप्ताह पश्चात् कतार के मध्य गुड़ाई करें। रोग संक्रमण होने पर कॉपरऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम/लीटर पानी की दर से घोलकर रोपणी में सिंचन करें।

■ मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म के प्रबंधन हेतु मक्के की शुष्क बोनी करें।

उद्यानिकी

■ गेंदा व गेलार्डिया की पौध तैयार करें।

■ पुराने उद्यानों में निंदाई-गुड़ाई व थाला बनाकर संतुलित मात्रा में खाद देने का कार्य करें।

■ फलदार वृक्षों में 4-5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।

■ वर्षा पूर्व फलदार वृक्षों पर बोर्डो पेस्टिंग का कार्य संपन्न करें।

■ किसान भाई नवीन उद्यानों की स्थापना हेतु सही भूमि का चयन, आम, अमरूद, नींबू, संतरा, आंवला, अनार आदि पौधों की उन्नत किस्मों का चयन व गड्ढों की खुदाई करें।

■ नवीन उद्यान की स्थापना में सामान्यतः उच्च सघन प्रणाली हेतु 5×5 मीटर व अतिसघन प्रणाली हेतु 3×3 मीटर कतारों एवं पौध से पौध की दूरी रखें। किस्मों का सही चयन वैज्ञानिकों की सलाह पर लें।

■ पपीते के बगीचे हेतु रोपड़ी तैयार करे।

■ ग्रीष्मकालीन सब्जियों में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करें ताकि कीटों का कम प्रकोप हो।

■ खरीफ हेतु बैंगन, टमाटर, मिर्च, अगेती फूलगोभी एवं खरीफ प्याज की पौध तैयार करें।

■ अधिक तापमान से नर्सरी को बचाने हेतु 50 प्रतिशत हरी शेडनेट का प्रयोग करें।

■ सब्जियों में उचित जल प्रबंधन करें।

■ कद्दूवर्गीय सब्जियों में अच्छे फल जमाव हेतु बोरेक्स 100 ग्राम/100 ली. का पर्णीय छिड़काव करें।

■ हल्दी एवं अदरक का मेढ़नाली पद्धति से रोपण करें।

■ सीमित संसाधन में अतिरिक्त आय हेतु मशरूम उत्पादन का कार्य करें।

पशुपालन

■ मुर्गीपालक गर्मी से मुर्गियों के बचाव हेतु शेड पर्दों से आधा ढक देवें। साथ ही ठंडे पानी की आपूर्ति रखें जिससे शेड में ठंडक बनी रहें।

■ मुर्गियों को रानीखेत नामक बीमारी से बचाव हेतु सभी मुर्गियों में इस बीमारी का टीकाकरण अवश्य करें।

■ पशुपालक अपने पशुओं को बाह्य एवं आंतरिक परजीवियों से बचाव के उपाय करें व स्वच्छ पानी ही पशुओं को पिलाएं।

■ दूध की बिक्री न हो पाने पर उसके उप-उत्पाद जैसे- मावा, पनीर, घी, चीज आदि बनाएं।

■ पशुओं में गलघोटू व लगंडी बुखार का टीका लगवाये।

कृषि अभियांत्रिकी

■ सोयाबीन की बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह जुताई करके तैयार करें। साथ ही खेत में समूचित जल निकासी की व्यवस्था बनाएं।

■ सोयाबीन की बुवाई रेज्ड बेड व मेढ़नाली पद्धति पर अवश्य करें। इसके लिए रेज्ड बेड प्लान्टर व रिज एवं फरो सीड ड्रिल का उपयोग करें।

किसानों से अपील की गई है कि खेतों में कृषि कार्य करते समय कोविड-19 (कोरोना) से बचाव हेतु शारीरिक दूरी 1.5 से 2.0 मीटर तक बनाएं रखें, मुंह पर मास्क लगाएं एवं साबुन से हाथ धोवें। अधिक तकनीकी जानकारी हेतु स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र पर सम्पर्क करें।

खरीफ फसलों की उन्नत किस्में

■ **सोयाबीन-** जे.एस. 20-34, जे.एस. 95-60, जे.एस. 20-29, जे.एस. 20-69, जे.एस. 20-98, एन.आर.सी. 86, आर.व्ही.एस. 2001-4, जे.एस. 335, जे.एस. 97-52, एन.आर.सी. 7, एन.आर.सी. 37 आदि।

■ **मक्का-** जे.एम. 216, जवाहर मक्का हाइब्रिड-1, एच.क्यू.पी.एम.-1, एच.क्यू.पी.एम.-3, जे.के.एम.एच. 4545, सुरभी, पी.ए.सी. 745 आदि।

■ **धान-** जे.आर.एच-5, जे.आर.एच-8, जे.आर.एच-19, पूसा बासमती-3ए पूसा सुगंधा-5ए पूसा 1121, क्रांति, एम.टी.यू 1010 आदि।

■ **अरहर-** राजीव लोचन, आई.सी.पी.एल. 87, आई.सी.पी.एच. 2671, आशा, टी.जे.टी. 501, राजेश्वरी आदि।

■ **मूंग-** पी.डी.एम. 139, एच.यू.एम.-1, एच.यू.एम.-12, एच.यू.एम.-16, गंगा-8, एम.एच. 421 आदि।

■ **उड़द-** एल.बी.जी.-20, आई.पी.यू. 2-43 आदि।

■ **कोदो-** जे.के. 98, जे.के. 13, जे.के. 155, जे.के. 48, जे.के. 439, जे.के. 41 आदि।

■ **कुटकी-** जे.के. 8, जे.के. 36 आदि।

■ **तिल-** टी.के.जी. 55, टी.के.जी. 72, टी.के.जी. 62, टी.के.जी. 63 आदि।

■ **रामतिल-** जे.एन.सी. 9, जे.एन.सी. 6, उटकमंड, यू.एन. 150 आदि।

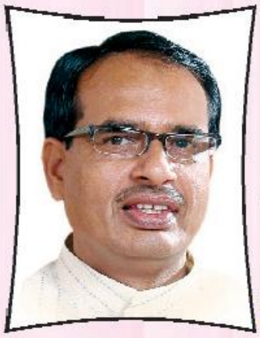

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

- किसान क्रेडिट कार्ड (फसल ऋण)
- ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों हेतु ऋण
- दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
- मत्स्य पालन हेतु ऋण
- स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए ऋण
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण
- कृषक को खेत पर शेड बनाने के लिए ऋण
- कम्बाइन हार्वेस्टर एवं रिपर कम बाइंडर क्रय ऋण

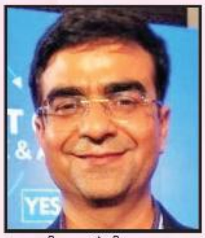
श्री चन्द्रमौली शुक्ला (कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता (उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश बार्चे (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री सत्यनारायण नायक (शा.प्र. स्टेशन रोड)
श्री सुरेशचंद्र गुजराती (शा.प्र. मंडी प्रांगण)
श्री दिलीप नागर (पर्य. मंडी प्रांगण)
श्री कमलसिंह झोरड़ (शा.प्र. बरोठा)
श्री एम.एल. चौधरी (पर्य. बरोठा)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. देवास, जि.देवास
श्री भगवानसिंह गोयल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नागदा, जि.देवास
श्री रमेशचंद्र नागर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. क्षिप्रा, जि.देवास
श्री श्याम पटेल (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बांगर, जि.देवास
श्री कृपालसिंह मकवाना (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बिजेपुर, जि.देवास
श्री महेन्द्रसिंह पंवार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बैरागढ़, जि.देवास
श्री इंदरसिंह गौड़ (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लोहारी, जि.देवास
श्री संजय दुबे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मकंदखेड़ी, जि.देवास
श्री मोहनसिंह चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. निपान्या, जि.देवास
श्री सत्यनारायण व्यास (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भड़ पिपल्या, जि.देवास
श्री जगदीश चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बिलावली, जि.देवास
श्री मनोज गौड़ (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. नापाखेड़ी, जि.देवास
श्री मुकेश मकवाना (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. खटाम्बा, जि.देवास
श्री धर्मेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजोदा, जि.देवास
श्री महेश जैन (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. भानगढ़, जि.देवास
श्री रफीक पठान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरोठा, जि.देवास
श्री राजेन्द्रसिंह चावड़ा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सिरोल्या, जि.देवास
श्री मधुलाल गुप्ता (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. खोकरिया, जि.देवास
श्री राजेन्द्रसिंह चावड़ा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. केलोद, जि.देवास
श्री रामगोपाल वर्मा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पटाड़ी, जि.देवास
श्री मदूलाल चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सल्लोड़, जि.देवास
श्री विष्णुप्रसाद मुकाती (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने दिलाई मंत्रियों को शपथ

भोपाल। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया था। राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 20 केबिनेट एवं 8 राज्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। केबिनेट मंत्री के रूप में श्री गोपाल भार्गव, श्री जगदीश देवड़ा, श्री विजय शाह, श्री बिसाहूलाल सिंह, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री एदल सिंह कंषाना, श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विश्वास सारंग, श्रीमती इमरती देवी, डॉ. प्रभुराम चौधरी, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्री प्रेम सिंह पटेल, श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सुश्री उषा ठाकुर, श्री अरविंद भदौरिया, डॉ. मोहन यादव, श्री हरदीप सिंह डंग और श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ने शपथ ली।

राज्यमंत्री के रूप में श्री भारत सिंह कुशवाहा, श्री इंदर सिंह परमार, श्री रामखेलावन पटेल, श्री राम किशोर कांवरे, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, श्री गिरिराज डंडौतिया, श्री सुरेश धाकड़ और श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में केन्द्रीय मंत्री कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायत श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता श्री थावरचंद गहलोत, केन्द्रीय राज्यमंत्री संस्कृति और पर्यटन श्री प्रहलाद पटेल, सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर सहित राज्य मंत्री मण्डल के सभी मंत्रीगण उपस्थित थे। शपथ विधि का संचालन मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने किया।

जनता के लिए पूरे परिश्रम से जुट जाएँ : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नवगठित मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर समस्त मंत्रियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनसे राज्य की जनता के हित में पूरे परिश्रम से जुटकर कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश की जनता का कल्याण सुनिश्चित करें। कोरोना से लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था भी धीरे-धीरे ठीक होगी और मध्यप्रदेश को बदलने में समय नहीं लगेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने गत तीन माह में राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रजेंटेशन द्वारा दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए हमें कार्य करना है। हम अपने लिए नहीं बल्कि आमजन के लिए इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए पूरी योग्यता, परिश्रम और तनमयता से कार्य करें। मुझे आशा है कि समस्त मंत्रीगण सौंपे गए उत्तरदायित्व को कर्मठता से पूरा करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि यह प्रयास होना चाहिए कि मेहनत की पराकाष्ठा हो, पारदर्शिता हो और प्रमाणिकता भी स्थापित हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें टीम के रूप में कार्य करना है। मौजूदा कोरोना संकट ने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। इसके बावजूद हम पूरी क्षमताओं से, आनंद और प्रसन्नता के साथ कार्य करें। स्नेह, सौजन्य, मित्रता, सहयोग की भावना के साथ खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखने और उन्हें विकास का लाभ पहुँचाने के पूरे प्रयत्न करें।

शपथ ग्रहण करते मंत्रिमंडल के सदस्य

इंदौर जिले से उषा ठाकुर बनी मंत्री

इंदौर। इंदौर जिले से महू विधायक उषा ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सुश्री ठाकुर पूर्व पार्षद, शिक्षा समिति की अध्यक्ष, भा.ज.युवा. मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य, राष्ट्र सेविका समिति, सांस्कृतिक जागरण मंच, हिन्दु जागरण मंच एवं पहल समग्र क्रांति चेतना मंच से संबद्ध रही हैं। वर्ष 2003 में बारहवीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की परामर्शदात्री समिति की सदस्य रहीं। 2013 और 2018 में पुनः निर्वाचित हुईं।

मंत्री पद की शपथ लेने के बाद इंदौर आई उषा ठाकुर का भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप सभी के स्नेह से मैंने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ लेना सरल होता है लेकिन उस दायित्व को पूरा करना कठिन होता है। आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक महेन्द्र हार्डिया, मधु वर्मा व अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सुश्री उषा ठाकुर ने पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से भी मुलाकात की और आशीर्वाद लिया।

सहकारी बैंकें अब आरबीआई के दायरे में

नई दिल्ली। अब व्यावसायिक बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंकों की निगरानी का अधिकार भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश लाने का निर्णय किया। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई को देश में 1,482 शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न-राज्यों में कारोबार करने वाले 48 सहकारी बैंकों के अंकेक्षण और प्रबंधन से जुड़े अधिकार मिल जाएंगे। हालांकि अध्यादेश पर छह महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है।

प्रकाश जावड़ेकर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, शहरी सहकारी और एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाले सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में लाए जा रहे हैं। व्यावसायिक बैंकों पर लागू होने वाले सभी निर्देश इन बैंकों पर भी लागू होंगे। इससे जमाकर्ताओं की रकम सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। फरवरी में सरकार ने कहा था शहरी सहकारी बैंकों का अंकेक्षण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और केंद्रीय बैंक द्वारा तय प्रबंधन से जुड़े सभी निर्देश भी इन पर लागू होंगे। आरबीआई के पास सहकारी बैंकों के निदेशकमंडल को दरकिनार करने का अधिकार होगा।

अध्यादेश पर राष्टपति की मुहर लगने के बाद आरबीआई ऐसे बैंकों के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए न्यूनतम पात्रता भी तय कर पाएगा। इन बैंकों को मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के लिए आरबीआई की अनुमति लेनी होगी। फिलहाल ऐसे बैंकों के प्रबंधन का चयन सहकारी इकाइयों द्वारा होता है और उनकी नियुक्ति पर आरबीआई का अधिक जोर नहीं चलता है।

सहकारी बैंकों में 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं के करीब 4.84 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। जावड़ेकर ने कहा, सहकारी बैंकों की पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऐसा देखा जाता है कि जमाकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और वे बैंकों के आगे लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। अब यह नहीं होगा।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दें वैज्ञानिक

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार और जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को सम्बोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी, जिससे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश में समृद्धि आएगी। श्री तोमर ने वैज्ञानिकों से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने व कठिनाइयां कम करने में योगदान देने का आह्वान किया।

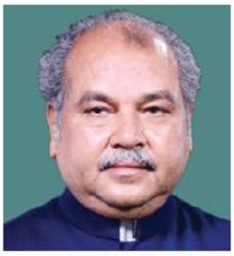

नरेन्द्रसिंह तोमर

श्री तोमर ने मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत केवल आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। किसानों ने साबित किया है कि वे किसी भी कठिन चुनौती का सामना करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी, जिसके वर्ष 2050 में 160 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है, अतः भारतीय प्लांट ब्रीडर्स और वैज्ञानिकों के समक्ष गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की चुनौती है, साथ ही बढ़ती आबादी को समुचित पोषणयुक्त भरपेट भोजन उपलब्ध कराना भी वैज्ञानिकों के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रोगरोधी व कीटरोधी उन्नत प्रजातियां विकसित करने की आवश्यकता है, जो सूखा, अत्यधिक तापमान, लवणीय व अम्लीय मृदा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने में समर्थ हों।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वेबिनार में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कम पानी में अधिक गुणवत्तापूर्ण उपज की पैदावार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते हैं कि जब तक हम गांवों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा। गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों को समृद्ध करना होगा। इनके सबके बाद भारत अन्य सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकेगा।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कोविड संकट में, जब विश्व अर्थव्यवस्था के पहिए की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, तब भारत के किसानों ने गांवों में उपलब्ध साधनों से ही बंपर पैदावार की, लॉकडाउन में फसल कटाई का काम सामान्य गति से जारी रहा और उपार्जन भी पिछली बार से अधिक रहा, खरीफ की फसलों की बुवाई भी पिछली बार से 45 प्रतिशत अधिक रही है। ये सब किसानों व हमारे गांवों की ताकत को प्रदर्शित करता है।

उपार्जन में नंबर वन आना किसानों के लिए गौरव की बात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ उर्पाजन में पूरे देश में नंबर वन आना सरकार और किसानों के लिये गौरव की बात है। कोरोना संकट के चलते इससे न केवल किसानों को बड़ी मदद मिली है अपितु प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी गतिशील हुई है। प्रदेश में काफी कम समय में रिकार्ड मात्रा में गेहूँ का उपार्जन बड़ी उपलब्धि है। मध्यप्रदेश पहली बार गेहूँ उपार्जन में पंजाब से आगे निकला है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित सभी संबंधित विभाग तथा पूरी टीम बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में गेहूँ उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री अनुपम राजन आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को गेहूँ उपार्जन संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों के छायाचित्रों का कोलाज मोमेन्टो के रूप में भेंट किया।

बैठक में बताया गया कि पंजाब में गेहूं उपार्जन का कार्य प्रायवेट आड़तियों के माध्यम से किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वहाँ के सिस्टम का विस्तृत अध्ययन किया जाए तथा वहाँ की बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि परिवहन से शेष गेहूँ का शीघ्र परिवहन कर उसे भंडार गृहों तक पहुंचाया जाए। बताया गया कि खरीदे गए गेहूँ की 95 प्रतिशत से अधिक मात्रा का परिवहन कर लिया गया है, शेष का जारी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस बार उपार्जन की एक विशेषता यह भी रही कि गत वर्षों की तुलना में काफी अधिक संख्या में लघु एवं सीमांत किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना गेहूँ बेचा। उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों में से 15 लाख 72 हजार किसानों ने अपना गेहूँ बेचा, जिनमें 5 लाख 4 हजार सीमांत किसान एवं 3 लाख 8 हजार लघु किसान शामिल थे।

अभी तक 127 लाख 81 हजार एम.टी. गेहूँ की खरीदी

प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि गेहूँ उपार्जन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। मध्यप्रदेश में अभी तक 127 लाख 81 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है, जहाँ अभी तक 127 लाख 67 हजार एम.टी. गेहूँ का उपार्जन हुआ है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जित गेहूँ का लगभग 33.03 प्रतिशत मध्यप्रदेश में उपार्जन किया गया है। पिछले वर्ष मध्यप्रदेश में 73.69 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था।

विश्व पर्यावरण दिवस पर राजभवन में पॉली हाउस शुरू

भोपाल। राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने राजभवन में उपलब्ध कचरे, गोबर, गो-मूत्र इत्यादि जैविक और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर कृषि एवं उद्यानिकी फसल के लिये खाद और कीटनाशकों का निर्माण किया जाये। श्री टंडन विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर आयोजित संरक्षित खेती के लिए निर्मित पॉली हाऊस शुभारम्भ के बाद उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे, आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी श्री पुष्कर सिंह एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

श्री टंडन ने कहा कि राजभवन के फल और पुष्प उद्यान आदर्श उद्यान के रुप में विकसित किये जाएं जो सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बने। उद्यान निर्माण और संचालन का मूल आधार आत्म निर्भरता हो। उन्होंने कहा सभी कार्य प्रदर्शनात्मक तरीके से किये जायें ताकि उन्हें देखकर दूसरों को जानकारी और कार्य करने की प्रेरणा मिलें। आधुनिक, जैविक, उद्यानिकी पद्धतियों का व्यवहारिक रूप देखने को मिले।

राजभवन पॉली हाऊस में वर्षभर सब्जियों का उत्पादन होगा। पॉली हाऊस में नियंत्रित वातावरण में खेती होने से फसल की उत्पादकता भी कई गुना अधिक होगी। यह कीट व्याधियों से भी मुक्त होती है। जैविक सब्जी उत्पादन होगा। रसायन और कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए संरक्षित और पारम्परिक खेती का व्यवहारिक स्वरूप तैयार किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के निवासी इस आधुनिक विधि से अपने घरों पर बिना मिट्टी के भी जरूरत के अनुसार सब्जियाँ उगा सकते हैं। राजभवन सब्जी, दूध, जैविक खाद और कीटनाशकों के उपयोग में आत्म निर्भर हो गया है। रसोई के लिए अधिकांश सब्जियाँ, दूध, घी, दही, छाछ, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि बाजार से नहीं खरीदे जायेंगे।

कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाके बंद होंगे

भोपाल। भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाको को बंद किया जाएगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 26 हजार कृषक मित्र भी पुनः बनाए जाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

कमल पटेल

कृषि मंत्री ने कहा कि सभी मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाये जाएं और मंडियों को अपग्रेड किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि किसानों से अवांछित तरीके से वसूली न होने पाए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री संदीप यादव और संचालक कृषि श्री संजीव सिंह उपस्थित रहे।

श्री पटेल ने विपणन वर्ष 2020-21 में चना उपार्जन का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखने और उपार्जन हेतु एस.एम.एस. लगातार जारी किये जाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कलेक्टरों द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण न होने के बावजूद उपार्जन केन्द्र बंद कर दिये हैं वे तत्काल उपार्जन केन्द्र चालू करें एवं संबंधित कलेक्टर्स से स्पष्टीकरण लिये जायें।

मंत्री श्री पटेल ने दमोह जिले में वर्ष 2018-19 में उड़द फसल की किसानों की बकाया राशि 27 करोड़ 96 लाख रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट 5 जून 2020 के अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मंडियों के अन्तर्राज्यीय 54 नाको को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। बैठक में संचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि पी.के.व्ही.वाय. योजना के लक्ष्य जारी किये जाये तथा कलस्टर के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सभी जिलों के परियोजना संचालक आत्मा को तत्संबंध में तत्काल आदेश जारी किये जाये।

श्री पटेल ने किसानों को आवश्यक सलाह और सुझाव देने के लिये कृषक मित्र योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक 2 गावों में एक कृषक मित्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 26 हजार कृषक मित्र पुनः बनाये जायेंगे। इसी प्रकार खण्ड समन्वयक, जिला समन्वयक एवं संभाग समन्वयक भी बनाये जायेंगे।

1 जुलाई से संचालित होगा 'किल कोरोना अभियान'

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान में सरकार और समाज साथ-साथ कार्य करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र भी बनाये जायेंगे, जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिये कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमिश्नर-कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि वे इस अभियान के लिए आवश्यक तैयारियाँ अभी से प्रारंभ कर दें। देश के इस अनूठे और बड़े अभियान के संचालन से अन्य प्रदेशों तक भी एक सार्थक संदेश पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आमजन से भी अपील की है कि 'किल कोरोना अभियान' में अपना सहयोग प्रदान करें। घर-घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें। इस सर्वे में महिला और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। सर्दी-खांसी जुकाम के साथ ही डेंगू, मलेरिया, डायरिया आदि के लक्षण पाये जाने पर भी जरूरी परामर्श और उपचार नागरिकों को मिल सकेगा। सार्थक एप का उपयोग कर इन जानकारियों की प्रविष्टि की जाएगी। कुल दस हजार दल कार्य करेंगे। सर्वे दल अनुमानित दस लाख घरों में रोज जाएंगे। एक दल करीब 100 घरों तक पहुंचेगा। राज्य की शत-प्रतिशत आबादी को इस सर्वे से कवर किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा देने का कार्य भी साथ-साथ चलेगा। विभिन्न तरह की प्रचार सामग्री और प्रत्यक्ष सम्पर्क कर नागरिकों को सर्वे दल के आने की सूचना देने का कार्य एडवांस टीम द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नागरिकों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

प्रदेश में करीब 3 लाख लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत जांच, उपचार, क्वारेंटाइन, सर्वेलांस, संक्रमित क्षेत्र के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित लोगों में चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।कोविड से संबंधित कार्यों की इस ट्रेनिंग में आशा वर्कर्स और वालंटियर्स भी शामिल हैं।

प्रदेश की 15 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल। भारत सरकार द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए हैं। मध्यप्रदेश की 15 पंचायतों को यह अवार्ड मिला है। दो जिला पंचायत नीमच, मंदसौर और दो जनपद पंचायत आलोट एवं होशंगाबाद सहित प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है। पंचायतों द्वारा सेवाओं के बेहतर प्रदाय पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है।

पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कारों में जिला पंचायत को प्रमाण-पत्र सहित 50 लाख रूपये, जनपद पंचायत को प्रमाण-पत्र सहित 25 लाख रूपये और ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण-पत्र के साथ पाँच लाख से 15 लाख तक के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को राजस्व आय में बढोत्तरी, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन करने वाली ग्राम पंचायतों में नीमच जिले की ग्राम पंचायत भरवड़िया, सागर जिले की दो ग्राम पंचायत मरामाधौ एवं तुमरी, इंदौर जिले की ग्राम पंचायत पोटलोद, होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत बाबईखुर्द, धार जिले की ग्राम पंचायत सुंदरेल, सीधी जिले की ग्राम पंचायत पनवार चौहानन, मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत पाड़लिया मारू, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत कंसर, सीहोर जिले की ग्राम पंचायत मूगली और रतलाम जिले की ग्राम पंचायत बरखेड़ी शामिल हैं।

इसी प्रकार पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर काम-काज में दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश को ई-पंचायत पुरस्कार-2020 भी मिला है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश को द्वितीय श्रेणी अंतर्गत वर्ष-2020 का ई-पंचायत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैंक ऋण का लक्ष्य निर्धारित करें। बैंकों की वार्षिक साख योजना में एस.एच.जी. कंपोनैंट को पृथक से दर्शाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को कम से कम ब्याज दर पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक ऋण दिलवाने के लिए योजना बनाई जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकतम 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़े।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैंकों की वार्षिक साख योजना 2020-21 का विमोचन भी किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, ए.सी.एस श्री मनोज श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, ए.सी.एस श्री मनोज गोविल तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम.डी. एवं सी.ई.ओ. श्री पल्लव महापात्र ने वी.सी. के माध्यम से बैठक को संबोधित किया।

वार्षिक साख योजना 2020-21 मुख्य बिन्दु
कुल लक्ष्य 1,89,250 करोड़ रूपये।
पिछले वर्ष के लक्ष्य से 8.03 प्रतिशत ज्यादा।
प्राथमिक क्षेत्र के लिए 1,76,217 करोड़ रूपये का लक्ष्य।
कृषि क्षेत्र के लिए 1,34,236 करोड़ रूपये का लक्ष्य।
नाबार्ड के पी.एल.पी का 89 प्रतिशत।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकर्स से कहा कि वे नए युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रूपये तक का ऋण, उनसे बिना कोलेटरल गारंटी लिए, उपलब्ध कराएं। अभी यह देखने में आ रहा है कि जो पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को अधिकतर बैंक ऋण दे रही हैं। योजना में राज्य सरकार गारंटी दे रही है। इसलिए आवेदक से कोई भी गारंटी संबंधी दस्तावेज न लिए जाएं। वी.सी. में मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं।

टिड्डी दल पर कीटनाशकों का छिड़काव कर किया नियंत्रण

भोपाल। प्रदेश के उज्जैन, शहडोल, जबलपुर एवं भोपाल संभागो में टिड्डी दल के सक्रिय होने पर इनके नियंत्रण के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि भोपाल संभाग के विदिशा जिले के ग्यारसपुर विकासखंड के ग्राम सिमरहार में लगभग 4 किमी आकार के एक टिड्डी दल का रात्रिकालीन ठहराव हुआ, जिस पर 2 फायर ब्रिगेड द्वारा लगभग 80 लीटर कीटनाशकों का छिड़काव कर नियंत्रण की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार उज्जैन संभाग के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा विकासखंड के पराना, गूजरखेड़ी एवं धनोला ग्राम एक टिड्डी दल पर 2 ट्रेक्टरचलित स्प्रेपंपों एवं 1 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर नियंत्रण की कार्यवाही की गई। जबलपुर संभाग के सिवनी जिले के कुरई विकासखंड के सकाटा ग्राम के वन क्षेत्र में 1 टिड्डी दल का रात्रिकालीन ठहराव हुआ। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम कालीदूधी एवं हर्रा में 1 टिड्डी दल के ठहराव की स्थिति में रात्रिकालीन 2 फायर ब्रिगेड द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर नियंत्रण की कार्यवाही की गई। सभी जिलों को टिड्डी दलों की सतत निगरानी रखने एवं नियंत्रण के लिये अनुभाग स्तर पर आवश्यक संसाधनों सहित तैयार रहने के लिये निर्देशित किया।

मानानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान
को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ
किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री ओ.पी. गुप्ता
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री विशेष श्रीवास्तव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से
श्री महेश शर्मा (शा.प्र. खाचरौद)
श्री वीरेन्द्र पंवार/श्री अंतरसिंह चौहान (पर्य. खाचरौद)
सेवा सह. संस्था मर्या. संदला, जि.उज्जैन
श्री ईश्वरलाल गोस्वामी (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. नापन, जि.उज्जैन
श्री वीरेन्द्रसिंह पंवार (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. चिरोला, जि.उज्जैन
श्री धर्मेन्द्रसिंह सोनगरा (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. नरसिंहगढ़, जि.उज्जैन
श्री नंदकिशोर राठौर (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. कनवास, जि.उज्जैन
श्री मनोज पाण्डे (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. पचलासी, जि.उज्जैन
श्री ओमप्रकाश पाटीदार (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. नरेड़ीपाता, जि.उज्जैन
श्री भगवती शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. भीकमपुर, जि.उज्जैन
श्री सुनील कुमार जैन (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. नघासी, जि.उज्जैन
श्री दीपसिंह डोडिया (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. मंडावदा, जि.उज्जैन
श्री कचरूलाल प्रजापति (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. सर्वोदय, जि.उज्जैन
श्री आनंदीलाल व्यास (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. बेहलोला, जि.उज्जैन
श्री राजेन्द्रसिंह पंवार (प्रबंधक)
सेवा सह. संस्था मर्या. कमठाना, जि.उज्जैन
श्री अंतरसिंह जाधव (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

चने का उपार्जन 30 जून तक होगा : कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने निर्देशित किया है कि चने के उपार्जन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाये। उन्होंने कहा कि चना, मसूर, सरसों का उपार्जन 30 जून तक होना है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंत्री श्री पटेल कृषि विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि ऐसे किसान, जो एसएमएस मिलने के बाद भी चना मण्डी तक नहीं ले जा पाये हैं, उन्हें विभाग द्वारा पुनः एसएमएस भेजे जायेंगे। वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर मण्डी में विक्रय कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि चना, मसूर, सरसों का उपार्जन आगामी 30 जून तक किया जायेगा। किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जायेगा।

बैठक में मूँग के पंजीयन, चना उपार्जन के भुगतान की प्रगति, फसल बीमा योजना, कमल सुविधा केन्द्र पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण, परम्परागत कृषि विकास योजना के लक्ष्य जारी करने की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि संचालक श्री संजीव सिंह भी मौजूद थे।

श्री पटेल ने प्रदेश के सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाले पंद्रह जिलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी कई जिलों में चना उपार्जन लक्ष्य से काफी कम है। अतः उपार्जन के कार्य में तेजी लाते हुए सम्पूर्ण उपार्जन तक खरीदी कार्य जारी रखा जाये। पोर्टल चालू रखते हुए किसानों को एसएमएस भेजे जायें, जिससे पंजीकृत किसान अपनी चने की उपज को मंडी आकर बेच सकें।

6.58 लाख मीट्रिक टन चना खरीदा

भोपाल। प्रदेश में किसानों से 6. 58 लाख मीट्रिक टन चना की खरीद की जा चुकी है। किसानों को इसके लिए 3700 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब तक एक लाख 30 हजार मीट्रिक टन तिवड़ा चना खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से किसानों से तिवड़ा युक्त चने की खरीदी का कार्य गत 2 सप्ताह में संपन्न हुआ और उपार्जित किये गये तिवड़ा चने की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूँ और चना को मिलाकर अनुमानित 30 हजार करोड रुपए का भुगतान किसानों को किया गया।

रायसेन जिले में खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध

उमाशंकर भार्गव

रायसेन। रायसेन जिले में खरीफ़ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि वर्तमान में रायसेन जिले को लगभग 16,500 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 10,700 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है। साथ ही 5,600 मीट्रिक टन यूरिया समितियों में उपलब्ध है। इसी प्रकार जिले को लगभग 24,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हो चुका है जिसमें से 17,200 मीट्रिक टन डीएपी किसानों को वितरित किया जा चुका है। डीएपी समितियों के पास भी फिलहाल 6,750 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। जिले को 1132 मीट्रिक टन सुपरफॉस्फेट भी प्राप्त हो चुका है जिसमें से 900 मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 232 मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट समितियों में उपलब्ध है।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1223 मीट्रिक टन एनपीके (कॉम्प्लेक्स) भी प्राप्त हो चुका है जिसमें से करीब 100 मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है जबकि 1123 मीट्रिक टन एनपीके समितियों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिले को हर 3 से 4 दिन के बीच में मंडीदीप और विदिशा में रैक के माध्यम से लगातार खाद उपलब्ध हो रहा है। पूरे जिले में कहीं भी खाद की कमी नहीं है। जिले में समितियों के पास डबल लॉक में तथा निजी खाद विक्रेताओं के पास वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध है। साथ ही रेलवे रैक के माध्यम से भी खाद प्राप्त हो रहा है।

कलेक्टर श्री भार्गव ने जानकारी दी कि इस वर्ष सम्पूर्ण खरीफ सीजन 2020 के लिये लगभग 32,000 मीट्रिक टन यूरिया, 38,000 मीट्रिक टन डीएपी, 8,000 मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट, 1500 मीट्रिक टन पोटाश, 1200 मीट्रिक टन कॉम्प्लेक्स (एनपीके) खाद की आवश्यकता होगी। यह आवश्कता सितंबर 2020 के लिये रहेगी।

फसल बीमा और सम्मान निधि के 4600 करोड़ से राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मध्यप्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्योग के क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्यों के माध्यम से सशक्त अर्थव्यवस्था के लिये अधिकतम प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य के बिन्दुओं पर मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के पश्चात चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में कोरोना संकट के फलस्वरूप लॉकडाउन की लगभग दो माह की अवधि में 4600 करोड़ रूपये की राशि किसानों के खाते में जमा कर उन्हें राहत प्रदान की जा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि योजना की राशि शामिल हैं।

प्रदेश में 115 लाख मेट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों का उपार्जन भी 2.13 लाख मेट्रिक टन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2990 करोड़ रूपये हितग्राहियों को दिये गये हैं। एफ.पी.ओ. (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिये भी कार्य-योजना बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे क्रम पर है। लॉकडाउन की अवधि में लगभग 85 लाख परिवारों को 1700 करोड़ रूपए का वितरण किया गया है।

अपेक्स बैंक को नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रूपए स्वीकृत किये गये हैं। खरीफ 2019 में दिये गये फसल ऋण से 16 लाख किसानों को करीब 47 करोड़ रूपये की ब्याज सहायता भारत सरकार से और समय पर ऋण अदायगी पर प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होने की आशा है। प्रदेश में किसानों को पात्रतानुसार चरणबद्ध कार्ययोजना में के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) की उपलब्धता रहेगी। कृषि अधोसंरचना फण्ड के संबंध में भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर कार्ययोजना के लिये कार्रवाई की जायेगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के क्षेत्र में अनेक गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में राज्यों को संस्थागत सहयोग के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। मध्यप्रदेश को लगभग 30 करोड़ सालाना अनुदान राशि मिलने का अनुमान है। प्रदेश में पशुओं में शत-प्रतिशत टीकाकरण और पशुओं की टैगिंग का कार्य होगा। सभी 290 लाख गौ और भैंस वंशीय पशुओं को टैग लगाने का कार्य चल भी रहा है। अब तक 70 लाख पशुओं को टैग लगाए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा करीब 50 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल, खाद्य और सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिये मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

निराकरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

बैतूल। कलेक्टर श्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा योजनांतर्गत जो भी शिकायतें प्राप्त होंगी, इन शिकायतों के निराकरण हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी प्राप्त शिकायतों का अगले दिन तक अनिवार्य रूप से निराकरण करेंगे। उप संचालक कृषि ने बताया कि नोडल अधिकारी के रूप में सहायक संचालक कृषि श्री दीपक कुमार सरियाम नामांकित किए गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर 7879835765 है। शिकायत के निराकरण हेतु संबंधित बैंक मैनेजर की भी जवाबदेही होगी। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री एमएल त्यागी सहित समिति सदस्य उपस्थित थे।

प्रदेश में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ 2020 के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण है। किसान किसी बात की चिंता न करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कृषि आदान 2020 संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री उमाकांत उमराव, एम.डी. मार्कफेड श्री पी.नरहरि आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खरीफ के लिए किसानों को अभी तक 8.25 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित किया जा चुका है। इसमें 3.69 मीट्रिक टन यूरिया, 3.19 मीट्रिक टन डी.ए.पी., 0.44 मीट्रिक टन कॉम्पलैक्स, 0.24 मीट्रिक टन एम.ओ.पी. एवं सुपर फास्फेट 0.69 मीट्रिक टन किसानों को वितरित कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि खरीफ 2020 के लिए प्रदेश में खाद का कुल लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसमें यूरिया का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन, डी.ए.पी. का 7 लाख मीट्रिक टन, कॉम्पलेक्स का 2 लाख मीट्रिक टन, एम.ओ.पी. का एक लाख मीट्रिक टन तथा सुपर फॉस्फेट का 4 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कृषि आदान संबंधी परेशानी होने पर वे कंट्रोल रूम 181 पर सूचित करें। उनकी समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा।

इंदौर में 3.53 करोड़ की लागत से आइस्क्रीम प्लांट तैयार

इंदौर। इंदौर स्थित सांची दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र में 3.53 करोड रुपए की लागत से आइसक्रीम प्लांट तैयार किया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मोतीसिंह पटेल, इंदौर दुग्ध संघ के संचालक गण श्री रामेश्वर गुर्जर,श्री कृपाल सिंह सेंधव, श्री विक्रम मुकाती, श्री प्रहलाद पटेल, श्री सुरेश पटेल, श्री रामेश्वर रघुवंशी, श्री किशोर परिहार, श्री महेंद्र चौधरी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल आदि उपस्थित थे।

दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए .एन. द्विवेदी द्वारा संघ की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गई। श्री मोतीसिंह पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश के समस्त दुग्ध संघो में इंदौर दुग्ध संघ ही दूध एवं क्रीम से रियल मिल्क आइसक्रीम का निर्माण करेगा। संघ द्वारा निर्मित रियल मिल्क आइसक्रीम पूरे प्रदेश में विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान दुग्ध संघ में स्टॉक हुये 65 करोड़ रुपये के दूध पावडर, मक्खन के विक्रय नही होने के कारण हो रही हानि के संबंध में भी अवगत कराया गया। श्री सिलावट ने आग्रह किया कि प्रदेश की जनता को पूर्व से साँची के उत्पाद बन रहे है उसी प्रकार उच्च गुणवत्ता की आइसक्रीम भी उपलब्ध करवाए। जिससे पूरे प्रदेश मे सांची ब्रांड आइस क्रीम की विश्वनीयता बनी रहे।

मुख्यमंत्री को किसानों की ओर से ग्रीष्मकालीन मूँग भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मंत्रालय में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा और होशंगाबाद क्षेत्र के किसानों की ओर से प्रतीक स्वरूप मूंग भेंट की। इस अंचल में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। किसानों और श्रमिकों को विभिन्न कार्यों से रोजगार भी मिला है। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कृषि मंत्री श्री पटेल के माध्यम से ग्रीष्मकालीन मूंग भेंट की। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हरदा जिले में 74 हजार 142 हेक्टेयर में और होशंगाबाद जिले में 1 लाख 2000 हेक्टेयर में इस तरह कुल 1 लाख 76 हजार 142 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन हुआ है। इस अंचल में ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार 10 से 12 क्विंटल हुई है जो एक उपलब्धि है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, खाद्य और सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह उपस्थित थीं।

2 करोड़ भोजन पैकेट व 3.64 लाख क्विंटल खाद्यान्न वितरित

भोपाल। प्रदेश में माईग्रेंट/ स्ट्रेंडेड माईग्रेंट लेबर को एसडीआरएफ मद से अब तक तीन लाख 64 हजार 700 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। खाद्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान को दी। श्री पासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य आपदा राहत कोष में राज्यों को आवंटित खाद्यान्न वितरण की राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक लाख 88 हजार लोगों को 2.02 करोड़ भोजन पैकेट एवं 83 लाख खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध करावाए गये हैं। राज्य शासन द्वारा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री भोजन हेल्प लाईन 01 अप्रैल से प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिव शेखर शुक्ला ने खाद्यान्न आवंटन एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी दी।

श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार की 'आत्म-निर्भर भारत योजना' के बारे में बताया कि इस योजना के अंतर्गत माईग्रेंट/स्ट्रेंडेड माईग्रेंट लेबर का चयन मोबाईल एप से किया जाएगा। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से हितग्राही का नाम, समग्र आईडी, आधार नंबर आदि की जानकारी भी संकलित करायी जा रही है। उचित मूल्य की दुकानों पर पींओएस मशीन पर प्रदर्शित करवाकर खाद्यान्न का आवंटन एवं वितरण कराया जाएगा।

प्रदेश के 10 लाख माईग्रेंट लेबर जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे, जिनमें से 9.5 लाख लेबर वापिस मध्यप्रदेश आ चुके है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के साथ श्रमिकों को वापस लाने के लिये व्यापक सुविधाये उपलब्ध करवाई है। इसी तरह अन्य राज्यों के 40 हजार लेबर में से लगभग 20 हजार लेबर अभी भी मध्यप्रदेश में निवासरत हैं। उन्होंने बताया कि चिन्हांकन की कार्रवाई पूर्ण होते ही जून माह में खाद्यान्न वितरण प्रारंभ करा दिया जाएगा।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने केन्द्र सरकार की वन नेशन - वन राशन कार्ड योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस महत्वावकांक्षी योजना से राशनकार्ड धारी देश में कहीं भी अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पहले से यह योजना क्रियान्वित रहती तो किसी भी आपदा में खाद्यान्न की परेशानी नहीं होती। श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था के तहत 3 लाख 39 हजार 951 हितग्राहियों द्वारा राशन प्राप्त किया गया। अभी तक 70 प्रतिशत हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग की जा चुकी है।

मानवीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान
को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ

- किसान क्रेडिट कार्ड (फसल ऋण)
- ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों हेतु ऋण
- दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
- मत्स्य पालन हेतु ऋण
- स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए ऋण
- स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण
- कृषक को खेत पर शेड बनाने के लिए ऋण
- कम्बाइन हार्वेस्टर एवं रिपर कम बाइंडर क्रय ऋण

श्री बी.एल. मकवाना (संयुक्त आयुक्त सहकारिता) | श्रीमती सुनीता गोठवाल (प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता) | श्री के.के. रायकवार (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री सुरेशचंद्र कारपेंटर (शा.प्र. बेरछा) श्री प्रहलादसिंह दसोरिया (शा.प्र. अरनियाकलां) श्री दौलतसिंह राठौड़ (शा.प्र. तनेड़िया)
श्री ईश्वरसिंह यादव (पर्य. बेरछा) श्री दूल्हेसिंह सोलंकी (पर्य. अरनियाकलां) श्री कैलाश जैन (पर्य. तनेड़िया)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बेरछा, जि. शाजापुर श्री शौकीन खाँ (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. अरनियाकलां, जि. शाजापुर श्री देवराज वर्मा (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. तनेड़िया, जि. आगर मालवा श्री संजय कारपेंटर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. रथभँवर, जि. शाजापुर श्री मणिशंकर मंडलोई (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. अरनियाखुर्द, जि. शाजापुर श्री माखनसिंह परमार (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कुबड़ियाखेड़ी, जि. शाजापुर श्री गोविन्दसिंह राठौर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. तिलावद गोविंद, जि. शाजापुर श्री अशोक कुमार गुप्ता (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बेरछा दातार, जि. शाजापुर श्री कैलाश नारायण खींची (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. झलारा, जि. शाजापुर श्री मोहनसिंह तंवर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. चौसला कुल्मी, जि. शाजापुर श्री बाबूलाल चौहान (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. ढाबला धौसी, जि. शाजापुर श्री भँवरलाल उमठ (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. नेवरीमाता, जि. शाजापुर श्री नारायणसिंह यादव (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बिरगोद, जि. शाजापुर श्री जगदीश वर्मा (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पोचानेर, जि. शाजापुर श्री श्रीकांत देशमुख (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पीपलोनकलां, जि. शाजापुर श्री महेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कमल्याखेड़ी, जि. शाजापुर श्री शशिकांत गोठी (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. सायल, जि. शाजापुर श्री शिवनारायण चंद्रवंशी (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. मलवासा, जि. शाजापुर श्री राधेश्याम राठौर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. सुंदरसी, जि. शाजापुर श्री सैयद साजिद अली (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. रोलाखेड़ी, जि. शाजापुर श्री संतोष परमार (प्रबंधक)	समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने राज्यपाल पद की शपथ ली

भोपाल। राज्यपाल उत्तरप्रदेश श्रीमती आनंदी बेन पटेल को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ राजभवन के सांदीपनि सभागार में दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री द्वय श्री कमलनाथ, श्री दिग्विजय सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा श्री बी.डी. शर्मा, सांसद श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा श्री सुहास भगत, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी एवं अत्यंत सीमित संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य जन उपस्थित थे। शपथ विधि का संचालन मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस ने किया। शपथ ग्रहण उपरांत राज्यपाल श्रीमती पटेल को सुरक्षा बल द्वारा गार्ड ऑफ आनर दिया गया।

सहकारिता मंत्री श्री राजपूत ने की रबी उपार्जन की समीक्षा

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने रबी उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निश्चित अवधि के पूर्व ही गेहूँ की रिकार्ड खरीदी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि खरीदी के बाद खाद्यान्न का परिवहन कर उसे गोदामों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था मानसून के पूर्व सुनिश्चित करें।

मंत्री श्री राजपूत मंत्रालय में अधिकारियों के साथ गेहूँ, चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी एवं भंडारण पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में लगभग 120 लाख मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा चुका है। इसके अलावा 2 लाख 75 हजार मीट्रिक टन चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया गया है। गेहूँ के उपार्जन में प्रदेश ने इस वर्ष कीर्तिमान स्थापित किया है, जो मध्यप्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक उपार्जन से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के 19 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था, जिसमें से अभी तक 15 लाख 36 हजार किसानों ने खरीदी केन्द्रों पर गेहूँ उपार्जन कर लाभ उठाया। इसके पूर्व अधिकतम 50 से 60 प्रतिशत किसानों की तुलना में 80 प्रतिशत किसानों ने अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेची।

श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का परिवहन कर उसका सुरक्षित भंडारण कराया जा चुका है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि बारदानों की कमी एक दो दिन में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए जिन खरीदी केन्द्रों पर अतिरिक्त बारदाने हैं उन्हें आवश्यकता वाले खरीदी केन्द्रों पर पहुँचाया जा रहा है। विभिन्न उर्वरकों तथा बीज के अग्रिम भंडारण की समीक्षा करते हुए श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में उर्वरक एवं बीज का भंडारण खरीफ 2020 की आवश्यकता अनुरूप है, किसानों को कमी नहीं होने दी जाएगी।

बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, संचालक खाद्य श्री अविनाश लवानिया, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति श्री अभिजीत अग्रवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्री चौहान की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को कोविड-19 के दौरान प्रदेश में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किये गये प्रयासों और उससे जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही इस वैश्विक महामारी से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार, लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आदि के बारे में भी विस्तार से बताया।

लगभग आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को दो पुस्तिकाएं - 'उम्मीद' और 'मध्यप्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास' भेंट की। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित 'उम्मीद' पुस्तिका में प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सुनियोजित और संवेदनशील पहल का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दूसरी पुस्तिका 'मध्यप्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास' में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सौ दिन के कार्यों का लेखा-जोखा दिया गया है। इसमें कोरोना महामारी से जंग को पराजित करने से लेकर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों तक का उल्लेख है। साथ ही इस पुस्तक में इस अवधि में किये गये सुधारों और नवाचारों का जिक्र भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों की सराहना करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए केन्द्र से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

खरीदी मण्डी शेड में ही होना सुनिश्चित करें : श्री पटेल

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन संबंधी समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि खरीदी का कार्य मण्डी शेड में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहाँ पर चना उपार्जन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वहाँ उपार्जन कार्य जारी रखा जाये।

मंत्री श्री पटेल ने ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल का पंजीयन 25 जून तक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चना, मसूर, सरसों की खरीदी की तिथि भारत सरकार की समर्थन मूल्य नीति के अनुसार 29 जुलाई तक होना संभावित है। बैठक में मंत्री श्री पटेल ने धार कलेक्टर द्वारा 6 जून को खरीदी कार्य बंद करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये। श्री पटेल ने परिवहन कार्य में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों से राशि काटने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन-जिन स्थानों पर परिवहन कार्य 72 घटे से अधिक देरी से प्रारंभ हुआ है, वहाँ अनिवार्य रूप से ट्रांसपोर्टरों से राशि काटी जाये। श्री पटेल ने बैठक में गत वर्ष प्रायवेट वेयर-हाउस पर बनाये गये खरीदी केन्द्रों, आधा प्रतिशत कमीशन राशि प्राप्त करने वाले वेयर-हाउस, वेयर हाउसों को दी गई राशि संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रमुख सचिव, सहकारिता को दिये।

मंत्री श्री पटेल ने मण्डी एक्ट में संशोधन के उपरांत सहकारी समितियों को उपार्जन से प्राप्त होने वाली राशि और होने वाले नुकसान का आकलन कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समितियों को नुकसान न हो, इसके लिये आवश्यक प्रबंध किये जायें। बैठक में प्रमुख सचिव, सहकारिता श्री शिवशेखर शुक्ला, एम.डी. मार्कफेड श्री पी. नरहरि, संचालक, कृषि श्री संजीव सिंह और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर बधाई दी। श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर बधाई दी। मुलाकात के दौरान श्री सिंधिया ने कोविड-19 के राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 30 लाख रुपये की राशि का चेक मुझे सौंपा। मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए आपके द्वारा दिये गये योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।

खरगोन में कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा

खरगोन। वाणिज्यकर आयुक्त श्री राघवेन्द्र सिंह तथा इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने इंदौर संभाग के खरगोन पहुंचकर कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये किये गये कार्यों, किये जा रहे कार्यों तथा भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने उपचार, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन, सेम्पलिंग, फीवर क्लीनिक आदि के कार्यों की जानकारी ली।

स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित समीक्षा बैठक में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार, संपर्क में आए व्यक्तियों के सैंपल, कंटेनमेंट एरिया, होम आईसोलेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे, फीवर क्लिनिक और आगामी कार्य योजना के संबंध में समीक्षा के बाद निर्देश दिए। बैठक के प्रारंभ में संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने अब तक की स्थिति में कोरोना के संक्रमण और उस पर की गई कार्यवाही की प्रशंसा की। वहीं वाणिज्यकर आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि सेवा करने का यही सही वक्त है। पूरे जीवन में शायद ही ऐसा कोई वक्त आएं। अब तक किए गए प्रयास वाकई सराहनीय है, लेकिन आगे भी थमना नहीं है। मेहनत और योजना के बल पर आगे बढ़ते हुए कार्य करना है। बैठक में कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बेनल, एएसपी श्री जितेंद्रसिंह पंवार, एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत, बड़वाह एसडीएम श्री मिलिंद ढ़ोके, सीएमएचओ डॉ. रजनी डावर, सिविल सर्जन डॉ. राजेंद्र जोशी, एसडीओपी ग्लेडविन ई-कार, डॉ. रेवाराम कोसले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इंदौर संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने अन्य जिलों के उदाहरण देते हुए बताया कि होम कोरेनटाईन का पालन नहीं करने पर किसी जिले में परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हुए है। ऐसी स्थिति का दोहराव न हो, इसके लिए जरूरी है कि ऐसा सिस्टम बने, जिसमें होम कोरेनटाईन का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अधिकारी पृथक रूप से उस घर का निरीक्षण करें। उसके पश्चात यदि आवश्यक व्यवस्था हो, तो ही अनुमति दें। इसके अलावा भी ऐसी व्यवस्था करें, जिससे निरंतर इस बात की संतुष्टि हो सके कि होम कोरेनटाईन का पालन किया जा रहा है। होम कोरेनटाईन के लिए पल-पल की जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए।

मंत्री श्री पटेल ने खरगोन की फल-सब्जी मंडी का किया ई-शुभारंभ

खरगोन। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खरगोन जिले की बलवाड़ी मंडी के नवनिर्मित अतिरिक्त प्रांगण का ई-लोकार्पण और फल-सब्जी मंडी का ई-शुभारंभ किया। मंत्री श्री पटेल ने 8 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से प्रथम चरण के पूर्ण हुए कार्यों का लोकार्पण भी किया है। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ की लागत से द्वितीय चरण के कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि फल-सब्जी मंडी का शुभारंभ होने से फल और सब्जी विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। अब वे बेहतर तरीके से अपना व्यापार कर सकेंगे। इस अवसर खरगोन में क्षेत्रीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल, नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री बालकृष्ण पाटीदार, विधायक श्री रवि जोशी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री विपिन गौर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में नवीन पदस्थापनाएँ

जे.एन. कंसोटिया

शिवशेखर शुक्ला

पी. नरहरि

तरुण पिथोड़े

पवन कुमार शर्मा

अविनाश लवानिया

श्रीकांत बनोठ

अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
एम. गोपाल रेड्डी	पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत	अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर
आई.सी.पी. केशरी	एसीएस वाणिज्यिक कर	उपाध्यक्ष एवीडीए, एसीएस नर्मदा घाटी विकास विभाग
अनुराग जैन	एसीएस वित्त	एसीएस वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विशेष आयुक्त समन्वय
मोहम्मद सुलेमान	एसीएस स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रवासी भारतीय विभाग	एसीएस स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, प्रवासी भारतीय विभाग गैस राहत
विनोद कुमार	उपाध्यक्ष एवीडीए, एसीएस अ.जा. कल्याण विभाग	एसीएस जीएडी
जे.एन. कंसोटिया	एसीएस पशुपालन	म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
डॉ. राजेश राजौरा	प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति	प्रमुख सचिव श्रम
मलय श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव लोनिवि, संसदीय कार्य, पर्यावरण एवं एप्को महानिदेशक	प्रमुख सचिव पीएचई, पर्यावरण एवं महानिदेशक एप्को
पंकज राग	प्रमुख सचिव संस्कृति	प्रमुख सचिव संसदीय कार्य, खेल एवं युवक कल्याण
अशोक शाह	प्रमुख सचिव श्रम	प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग
मनोज गोविल	प्रमुख सचिव वित्त	प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर
मनु श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	प्रशासकीय सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर, ऊर्जा एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
कल्पना श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव म.प्र. शासन	प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
संजय दुबे	प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास	प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
नीरज मंडलोई	प्र.स. खनिज एवं उच्च शिक्षा	प्रमुख सचिव लोनिवि
अनुपम राजन	प्रमुख सचिव महिल एवं बाल विकास विभाग	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एवं जनसंपर्क का अति.प्रभार
संजय कुमार शुक्ला	प्रमुख सचिव पीएचई, चिकित्सा शिक्षा, एमडी जल निगम	प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश, चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार
डॉ.पल्लवी गोविल	प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं गैस राहत	प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण एवं अ.जा.कल्याण
दीपाली रस्तोगी	प्रमुख सचिव आ.जा.कल्याण	प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, तकनीकी शिक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यम
शिवशेखर शुक्ला	प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, संस्कृति, संचालक स्वराज संस्थान
प्रतीक हजेला	प्रमुख सचिव म.प्र. शासन	प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण
डी.पी. आहूजा	प्रमुख सचिव पशुपालन	प्रमुख सचिव जल संसाधन
नीतेश व्यास	एमडी म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर प्रमुख सचिव ऊर्जा	प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, प्रशासक राजधानी परि. एमडी मेट्रो रेल कंपनी
फैज अहमद किदवई	प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा पर्यटन, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन	प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि, आयुक्त खाद्य सुरक्षा
अमित राठौर	पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक	प्रमुख सचिव वित्त एवं संचालक संस्थागत, वित्त
करलिर देशमुख	आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त, सचिव वित्त	सचिव खनिज साधन, एमडी खनिज निगम एवं पंजीयन महानिरीक्षक व अधीक्षक मुद्रांक
सोनाली वायंगणकर	एमडी महिला वित्त एवं विकास निगम	संचालक प्रशासन अकादमी
डॉ. एम.के. अग्रवाल	आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएँ	सचिव आयुक्त तथा संस्थाएँ, सचिव आयुष आयुक्त सह संचा. भारतीय चिकि. पद्धति होम्योपैथी
रेनू तिवारी	कमिश्नर चंबल संभाग मुरैना	आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
पी. नरहरि	आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, जनसंपर्क एवं एमडी माध्यम	एमडी राज्य सहकारी विपणन संघ, आयुक्त नगरीय प्रशा. एवं विकास का अतिरिक्त प्रभार
राजेश बहुगुणा	आयुक्त आबकारी ग्वालियर	सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर
मोहनलाल मीना	ओएसडी मंत्रालय	एमडी म.प्र. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
राजीव चंद्र दुबे	सचिव जेल एवं स्वास्थ्य	आयुक्त आबकारी ग्वालियर
अजीत कुमार	संचालक प्रशासन अकादमी सचिव उच्च शिक्षा	आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश
रविन्द्र कुमार मिश्रा	सचिव म.प्र . शासन	आयुक्त रेशम
डॉ. श्रीनिवास शर्मा	सचिव म.प्र. शासन	सचिव जीएडी
श्रीमन शुक्ला	एमडी राज्य सहकारी विपणन संघ, एमडी उद्योग विकास नि.	एमडी सड़क विकास निगम,सीईओ म.प्र. इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी
रवीन्द्र सिंह	सचिव म.प्र. शासन	ओएसडी सह सचिव रा.सूचना आयोग
सुदाम पी. खाड़े	संचालक स्वास्थ्य, एमडी सड़क विकास निगम	अपर सचिव जनसंपर्क एवं एमडी माध्यम, आयुक्त जनसंपर्क
स्वाति मीणा नायक	मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	संचा. महिला एवं बाल विकास मिशन संचालक अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण
स्वतंत्र कुमार सिंह	संचालक नगर एवं ग्राम निवेश, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास	अपर आयुक्त नगरीय प्रशा.एवं विकास, आयुक्त नगरीय प्रशा. एवं विकास का अतिरिक्त प्रभार
शशांक मिश्र	अपर सचिव म.प्र. शासन	सीईओ ग्रामीण सड़क वि.प्रा.
छवि भारद्वाज	अपर आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
कृष्णगोपाल तिवारी	संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	उपसचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
विशेष गढ़पाले	सीईओ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	एमडी मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
तेजस्वी एस.नायक	अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास	प्रबंध संचालक म.प्र. जल निगम
डॉ. विजय कुमार जे.	संचालक स्वास्थ्य	संचालक स्वास्थ्य
राधेश्याम जुलानिया	पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

श्रीमती सलीना सिंह	अध्यक्ष, मा.शि.म.	अध्यक्ष, प्रोफे.एग्जामिनेशन बोर्ड
सूफिया फारूकी वली	प्रबंध संचालक, मप्र बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल	संचालक, प्रोफे.एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मप्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार)
नरेन्द्र सूर्यवंशी	अपर कलेक्टर, देवास	उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा
राजकुमार खत्री	उप सचिव, राजस्व विभाग	उपसचिव,रानिआयोग, भोपाल
आशीष कुमार	आयुक्त ननि जबलपुर	उपसचिव उद्यानिकी विभाग
जगदीशचंद्र जटिया	उपसचिव मप्र शासन	उपसचिव महिला बाल विकास
संजय कुमार	कलेक्टर आगर मालवा	उपसचिव मप्र शासन
छोटे सिंह	उपसचिव मप्र शासन	उपसचिव श्रम विभाग
बी. विजय दत्ता	उपसचिव मप्र शासन	उपसचिव औद्योगिक नीति निवेश
डॉ. श्रीकांत पाण्डेय	अपर सचिव म.प्र . शासन	अपर सचिव राजस्व विभाग
दीपक कुमार सक्सेना	उपसचिव मप्र शासन	प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास नि.
प्रदीप जैन	सीईओ, स्मार्ट सिटी, उज्जैन	सीजीएम, मप्र सविनि, भोपाल
कृष्णकुमार रावत	संयुक्त कलेक्टर, सीहोर	उपायुक्त, राजस्व, रीवा संभाग
तरुण पिथोड़े	कलेक्टर भोपाल	संचालक खाद्य नागरिक आ.
श्रीकांत बनोठ	उपसचिव मप्र शासन	प्रबंध सं. कृषि उद्योग विकास निगम
भास्कर लक्षकार	उपसचिव राजस्व	प्रबंध संचालक लघु उद्योग निगम
बसंत कुर्रे	उपसचिव मप्र शासन	संचालक भोपाल गैस त्रासदी पुन.
अजय सिंह गंगवार	कमिश्नर सागर संभाग	सचिव म.प्र . शासन
आकाश त्रिपाठी	कमिश्नर इंदौर संभाग	प्रबंध संचालक मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि. जबलपुर
नरेश पाल कुमार	आयुक्त महिला बाल विकास	कमिश्नर शहडोल संभाग
डॉ. पवन कुमार शर्मा	आयुक्त नर्मदा घा.वि. प्र ाधि.	कमिश्नर इंदौर संभाग
जनक कुमार जैन	सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर	कमिश्नर सागर संभाग
अविनाश लवानिया	संचालक खाद्य नागरिक आ.	कलेक्टर भोपाल
आलोक कुमार सिंह	उपसचिव योजना आर्थिक सां.	कलेक्टर धार
इलैया राजा टी.	संचालक सू.ल.म. उद्यम	कलेक्टर रीवा
वेद प्रकाश	संचालक भोपाल गैस त्रासदी	कलेक्टर नरसिंहपुर
अनिल कुमार खरे	उपसचिव लोनिवि	कलेक्टर मंडला
चन्द्रमौलि शुक्ला	उपसचिव औद्योगिक नीति	कलेक्टर देवास
राजीव रंजन मीना	प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास	कलेक्टर सिंगरौली
अवधेश शर्मा	उपसचिव मुख्यमंत्री कार्यालय	कलेक्टर आगर मालवा
कैलाश वानखेड़े	अपर कलेक्टर, इंदौर	अपर कलेक्टर, बुरहानपुर
चंद्रशेखर शुक्ला	सीईओ जिपं, अशोकनगर	अपर कलेक्टर, भोपाल
डॉ. अभय वेडेकर	मुख्य प्रशा. अधिकारी, रैरा	अपर कलेक्टर, इंदौर
सरोधन सिंह	सीईओ, जिपं, अनूपपुर	अपर कलेक्टर, अनूपपुर
अवि प्रसाद	सीईओ जिपं रायसेन	अपर कलेक्टर उज्जैन
अर्पित वर्मा	आयुक्त ननि रीवा	अपर कलेक्टर शहडोल
आशीष तिवारी	एसडीएम कोलारस	अपर कलेक्टर ग्वालियर
आशीष सांगवान	एसडीएम बैरसिया	अपर कलेक्टर राजगढ़
अरुण विश्वकर्मा	सीईओ जिपं सीहोर	सीईओ स्मार्ट सिटी भोपाल
सोमेश मिश्रा	उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सीईओ जिला पंचायत, बड़वानी
पी.सी. शर्मा	संयुक्त आयुक्त, रीवा	सीईओ, जिपं रायसेन
नीलेश पारीख	संयुक्त आयुक्त, भोपाल	सीईओ, जिपं, गुना
मिलिंद नागदेवे	अपर कलेक्टर, शहडोल	सीईओ, जिपं, अनूपपुर
अतेंद्र सिंह गुर्जर	अपर कलेक्टर, भोपाल	सीईओ, जिपं, दतिया
भगवान सिंह जाटव	सीईओ, जिपं, दतिया	सीईओ, जिपं, अशोकनगर
अनूप कुमार सिंह	अपर कलेक्टर ग्वालियर	आयुक्त ननि जबलपुर
मृणाल मीना	सीईओ जिपं राजगढ़	आयुक्त ननि रीवा
वी.एस. चौधरी	कलेक्टर सिंगरौली	आयुक्त नगर निगम भोपाल

जनसंपर्क विभाग में भी तबादले

श्रवण कुमार सिंह	उपसंचालक, देवास	जनसंपर्क संचालनालय भोपाल
लक्ष्मण सिंह	उपसंचालक, रीवा	जनसंपर्क संचालनालय भोपाल
प्रलय श्रीवास्तव	उपसंचालक संचालनालय	सं.ज.सं.का. सागर
सुनील वर्मा	सहा. संचालक संचालनालय	सं.ज.सं.का. दमोह
अंकुश मिश्रा	सहायक संचालक अनूपपुर	जनसंपर्क संचालनालय भोपाल
आनंद मोहन गुप्ता	सहा. जनसंपर्क अधिकारी	सं.ज.सं.का. देवास
याशिक अहमद कुरैशी	सहा. सूचना अधिकारी दमोह	जनसंपर्क संचालनालय भोपाल

आशुतोष प्रताप सिंह द्वारा संचालक जनसम्पर्क का पदभार ग्रहण

भोपाल। श्री आशुतोष प्रताप सिंह ने संचालक जनसम्पर्क का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अपर संचालक श्री एल.आर. सिसोदिया, श्री सुरेश गुप्ता, श्री मंगला मिश्रा और श्री एच.एल. चौधरी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्री सक्सेना सहकारिता आयुक्त बने

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्री आशीष सक्सेना को सहकारिता आयुक्त बनाया गया है। साथ ही राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें सौंपा गया है। वर्ष 2003 बैच के अधिकारी श्री सक्सेना इसके पूर्व मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव पद पर पदस्थ थे।

सहकारी बैंक सीईओ के तबादले

विशेष श्रीवास्तव

अनूप जैन

ए.के. हरसोला

के.के. रायकवार

भोपाल। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किये गये हैं। श्री विशेष श्रीवास्तव को सीधी से उज्जैन, श्री अनूप जैन को राजगढ़ से खरगोन, श्री ए.के. हरसोला को रायसेन से खंडवा, आलोक यादव उज्जैन से सीधी, श्री एन.यू. सिद्दीकी खंडवा से रायसेन एवं श्री के.के. रायकवार को खरगोन से शाजापुर पदस्थ किया गया।

राधेश्याम मण्डलोई साँवेर एसडीओ

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश जारी कर संयुक्त कलेक्टर श्री राधेश्याम मण्डलोई को सांवेर क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी बनाया है। इसी तरह खुडेल क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी का कार्य डिप्टी कलेक्टर श्री रवीश श्रीवास्तव को सौंपा गया है।

गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराना प्राथमिकता

भोपाल। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। कृषक हित में लक्ष्य आधारित योजना बनाए और मैदानी स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करे। उक्त निर्देश संभागायुक्त श्री कविंद्र कियावत ने बैठक के दौरान सभी संबंधित संभागीय स्तर के अधिकारियों को दिए। संभागीय कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में पशुपालन और डेयरी, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, उद्यानिकी, सहकारिता और कृषि एवं संबद्ध संस्थाएँ के अधिकारियों को जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

कृषि एवं संबद्ध संस्थाओं को निर्देश दिये कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराएँ। सभी अधिकारी जिलों में सतत भ्रमण करें। खाद, बीज और कीटनाशक की नियमित जांच करें। अमानक बीजों पर रोक लगाएं। स्पायराल ग्रेडर का उपयोग कर अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध कराए और उत्पादन बढ़ाए। धान फसल के लिए पेडी ट्रांसप्लांटर का डेमो किसानों को दें इससे किसानों को ही लाभ है। निजी कृषक चाहे तो इसे खरीद सकते हैं।

भोपाल दुग्ध संघ वर्तमान में 3 लाख 8 हजार दुग्ध संग्रहित कर रहा है। 5 लाख लीटर दुग्ध संग्रहण का लक्ष्य लेकर कार्य करें और निश्चित समय-सीमा में प्राप्त करे। पशु बीमा योजना का कवरेज बढ़ाएँ। पशु कल्याण समिति की राशि के माध्यम से पशुओं के आहार के लिए वर्तमान समय में भूसा खरीदें। जिलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से संपर्क कर एनआरएलएम समूहों को स्व- सहायता समूह से जोड़े। सभी गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन लगवाना सुनिश्चित करें। राजगढ़ और सीहोर जिले में फसल चक्र के माध्यम से मसाले और औषधि फसलों का क्षेत्र विस्तार करें। उद्यानिकी फसलों के रकबे को राजस्व रिकॉर्ड में अभियान चलाकर दर्ज करवाएं।

सहकारी बैंकें जिले वार, बैंक वार और ब्रांच बार अपनी वसूली की समीक्षा करें। सामान्य वसूली और डिफाल्टर की राशि वसूली पर अधिक ध्यान दें। संभाग में सभी किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो इसका विशेष ध्यान रखें। स्वयं हर जिले में जाएं और निरीक्षण करें। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

श्री कियावत ने कहा यही समय है कि हम फील्ड में जाए और अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करें। आप सभी अपने कार्य के दौरान पूर्ण सावधानी बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क लगाए रखें। जनहित की जिम्मेदारियों को हमें गंभीरता से निभाना है इसके साथ ही हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखना है।

बैठक में उपायुक्त (विकास) श्री अनिल कुमार द्विवेदी, उपायुक्त श्रीमती संजू कुमारी, संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री आर.आर. सिंह, उपायुक्त सहकारिता श्री विनोद सिंह, संयुक्त संचालक कृषि श्री बी.एल. बिलैया, उपसंचालक कृषि श्री शिवनारायण सोनानिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ श्री के.के. सक्सेना सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कुक्कुट उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित

भोपाल। पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुर्गियों से कोरोना फैलने की बात निराधार और तथ्यों से परे है। पशुपालन विभाग ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से अभिमत प्राप्त किया है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि कुक्कुट उत्पादों से किसी भी प्रकार से कोरोना फैलने की खबर पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन है तथा कुक्कुट उत्पादों का सेवन पूरी तरह से सुरक्षित है। संचालक पशुपालन डॉ. आर.के. रोकड़े ने बताया कि भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के सचिवों को पत्र के जरिये सूचित किया है कि मुर्गी पालन से मनुष्यों में कोरोना का संक्रमण नहीं होता तथा वर्तमान में इनका सेवन न केवल सुरक्षित है बल्कि यह प्रोटीन से भरपूर सस्ता खाद्य पदार्थ है जो मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डॉ. रोकड़े ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में कुक्कुट उत्पादों का उपयोग नहीं करने तथा मुर्गी पालन फार्म को शीघ्र बंद करने जैसे कोई दिशा-निर्देश या चेतावनी-पत्र जारी नहीं किया है।

प्रदेश में 138 लाख हैक्टेयर में होगी खरीफ की बोवनी

भोपाल। प्रदेश में मानसून के आने की खबरों के साथ खरीफ की बोवनी भी शुरू हो चुकी है। राज्य में इस वर्ष 138.27 लाख हैक्टेयर में खरीफ फसल लेने की तैयारी चल रही है। लगभग 25 लाख टन से अधिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि म.प्र. में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118.50 लाख हैक्टेयर है। इस वर्ष 138.27 लाख हैक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रमुख फसल सोयाबीन 56 लाख हैक्टेयर में ली जाएगी जबकि पिछले वर्ष 55.24 लाख हैक्टेयर में की गई थी। दूसरी प्रमुख फसल धान 25 लाख हैक्टेयर में ली जाएगी जबकि गत वर्ष धान की बोवनी 24.60 लाख हैक्टेयर में हुई थी। अन्य प्रमुख फसलों में मक्का 16 लाख हैक्टेयर में, बाजरा 3 लाख, अरहर 5.26 लाख, उड़द 16.50 लाख, मूँग 2 लाख, मूँगफली 2.22 लाख, तिल 3.14 लाख एवं कपास 6.09 लाख हैक्टेयर में बोई जाएगी।

खरीफ 2020 का बुवाई लक्ष्य

फसल	लक्ष्य
धान	25.00 लाख हैक्टेयर
ज्वार	0.50 लाख हैक्टेयर
मक्का	16.00 लाख हैक्टेयर
बाजरा	3.00 लाख हैक्टेयर
तुवर	5.26 लाख हैक्टेयर
उड़द	16.50 लाख हैक्टेयर
मूँग	2.00 लाख हैक्टेयर
सोयाबीन	56.00 लाख हैक्टेयर
तिल	3.14 लाख हैक्टेयर
कपास	6.09 लाख हैक्टेयर

इंदौर जिले में खरीफ बुआई जारी

इंदौर जिले में इस वर्ष इस माह शुरूआती दौर में हुई वर्षा से खरीफ की बोनी के लिये अनुकूल वातावरण बना है। इसके फलस्वरूप किसानों ने बोनी का काम समय पर शुरू कर दिया था। जिले में वर्तमान में खरीफ की बोनी का काम तेजी से जारी है। उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल ने बताया कि जिले में इस वर्ष लगभग ढ़ाई लाख हेक्टेयर रकबे में खरीफ की आच्छादित होगी। गत वर्ष खरीफ की बोनी 2 लाख 49 हजार 515 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। जिले में इस वर्ष भी सोयाबीन की बुआई मुख्य रूप से की जा रही है। सोयाबीन की फसल 2 लाख 13 हजार 350 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य हैं। जिले में बोनी का काम लगभग 95 प्रतिशत पूरा हो गया है। कृषि विभाग द्वारा खरीफ की बुआई के मद्देनजर किसानों को खाद, बीज सहित अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिये व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले में इस वर्ष खरीफ की बोनी 2 लाख 49 हजार 984 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य है।

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बधाई
मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर
माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान
को हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री जगदीश कन्नौज (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री अम्बरीश वैद्य (उपायुक्त सहकारिता झाबुआ)
श्री बी.एस. कोठारी (उपायुक्त सहकारिता अलीराजपुर)
श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक इन्दौर)
श्री डी.आर. सरोठिया (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
श्री पारसिंह मुनिया (शा.प्र. थांदला), श्री गुलाबसिंह निनामा (पर्य. थांदला), श्री मन्नूसिंह खतेड़िया (शा.प्र. मेघनगर), श्री संजय नागर (पर्य. मेघनगर)
श्री जामसिंह भाभर (शा.प्र. अलीराजपुर), श्री महेन्द्रसिंह राठौर (पर्य. अलीराजपुर), श्री गमलसिंह पटेल (शा.प्र. भाभरा), श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़ (पर्य. भाभरा)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. थांदला, जि.झाबुआ श्री विक्रम बैरागी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. परवलिया, जि.झाबुआ श्री अर्जुन हाड़ा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. हरिनगर, जि.झाबुआ श्री श्रीराम श्रीवास्तव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. खजूरी, जि.झाबुआ श्री निहालसिंह कन्नौज (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ी धामनी, जि.झाबुआ श्री राजेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. काकनवानी, जि.झाबुआ श्री गुलाबसिंह निनामा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. मेघनगर, जि.झाबुआ श्री शंकरसिंह नायक (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. रम्भापुर, जि.झाबुआ श्री गरवरसिंह कठोता (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. मदरानी, जि.झाबुआ श्री मानसिंह वसुनिया (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. नौगाँवा, जि.झाबुआ श्री दिनेश बैरागी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. पंथ पिपल्या, जि.झाबुआ श्री इन्दरसिंह राठौर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. मांडली, जि.झाबुआ श्री नरवरसिंह हाड़ा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. अलीराजपुर, जि.झाबुआ श्री जगदीश डाबर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. आम्बुआ, जि.झाबुआ श्री महेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरझाड़, जि.झाबुआ श्री महेन्द्रसिंह राठौर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. नानपुर, जि.झाबुआ श्री बालाप्रसाद प्रजापति (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. चाँदपुर, जि.झाबुआ श्री मुकामसिंह बघेल (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोरवां, जि.झाबुआ श्री मुकामसिंह बघेल (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरखड़, जि.झाबुआ श्री दिलीप वाणी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. भाभरा, जि.झाबुआ श्री जगदीश पांचाल (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरझर, जि.झाबुआ श्री भेरूसिंह गाडरिया (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. झीरण, जि.झाबुआ श्री शैलेन्द्रसिंह राठौड़ (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. सेजवाड़ा, जि.झाबुआ श्री कैलाशचंद्र कायस्थ (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

3.20 करोड़ की नर्मदा पेयजल पाइप लाइन का भूमिपूजन

इंदौर। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के अथक प्रयासों से कनाड़िया क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिये बड़ी सौगात मिलेगी। मंत्री श्री सिलावट ने ग्राम कनाड़िया में तीन करोड़ 20 लाख रुपये लागत की नर्मदा पाइप लाइन कार्य का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री रमेश मैंदोला, पूर्व विधायक डॉ. राजेश सोनकर, श्री मधू वर्मा, श्री सावन सोनकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रुप से मौजूद थे। अमृत योजना अंतर्गत कनाडिया गांव में 4 कि.मी. क्षेत्र में 400 एमएम व्यास की 3 करोड 20 लाख की लागत से नर्मदा जलप्रदाय लाईन डालने का कार्य का प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट एवं सांसद श्री शंकर लालवानी द्वारा भूमिपूजन किया गया है। इस अवसर पर विधायक श्री रमैश मैन्दोला, पूर्व विधायक श्री राजेश सोनकर, पूर्व आईडीए अध्यक्ष श्री मधु वर्मा, श्री सावन सोनकर, बडी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकगण उपस्थित थे। श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में सतत विकास हुआ है, इसी क्रम में आज अमृत योजना के अंतर्गत कनाडिया गांव में 4 कि.मी. क्षेत्र में 400 एमएम व्यास की 3 करोड 20 लाख की लागत से नर्मदा जलप्रदाय लाईन डालने का कार्य का भूमिपूजन किया गया। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा पहले कनाडिया और फिर सांवेर भी आएगी। सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि माँ नर्मदा का इस क्षेत्र में आगमन हुआ है। उनके आगमन पर करोडो की लागत से पाईप डालने के कार्य की शुरूआत भी हुई है। विधायक श्री रमेश मैन्दोला ने कहा कि कनाडिया गांव के विकास में आज का दिन बहुत ही अहम है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शासन द्वारा क्षेत्र के सभी किसानो का सारा गेहूँ खरीद लिया गया है।

लायसेंस निलंबित

खरगौन। मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव का निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषकों को बीज प्रदाय नहीं करने पर बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने बताया कि कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड तथा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादिय चोली से प्राप्त शिकायत के अनुसार मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव द्वारा सोयाबीन बीज निम्न क्वालिटी का प्रदाय किया जा रहा है। इस कारण किसानों द्वारा सोयाबीन बीज विक्रय कर खेतों में बोने के 5 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होने एवं जमीन में ही सड़ा हुआ पाया गया। कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कृषकों को बीज प्रदाय नहीं करने पर बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेष 1983 के नियम 15 एवं 15(क) (स) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भीकनगांव का बीज लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं जिला स्तरीय जांच दल गठित कर संपूर्ण जांच कर एक सप्ताह में कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए है। यह दल खेतों का निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट व अपना अभिमत प्रस्तुत करेगा।

बीज वितरित

खण्डवा। उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता द्वारा बताया गया कि म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला खण्डवा द्वारा कृषकों के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत अन्नपूर्णा व सूरजधारा योजना में 102.20 क्विंटल संकर मक्का बीज, सूरजधारा योजना में 396.30 क्विंटल सोयाबीन बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को वितरित किया गया। बीजग्राम योजना अंतर्गत 780 क्विंटल सोयाबीन बीज, 9 क्विंटल मूंग तथा 9 क्विंटल अरहर का बीज 60 प्रतिशत् अनुदान पर वितरित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 225 क्विंटल सोयाबीन बीज, 20 क्विंटल उडद, 20 क्विंटल अरहर एवं 3 क्विंटल मक्का बीज का प्रदर्शन प्लाट तैयार करने के लिये कृषकों को वितरित किये।

अमरूद की नीलामी हेतु निविदाएँ

उज्जैन। उप संचालक उद्यानिकी द्वारा जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 हेतु शासकीय उद्यान कोठी नर्सरी पर उपलब्ध अमरूद सघन फलोद्यान फलबहार संख्या 800 नग की नीलामी के लिये सीलबन्द निविदाएं उप संचालक कार्यालय उद्यानिकी में आमंत्रित की गई है। प्राप्त निविदाएं उव्यापारियों के समक्ष खोली जायेंगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर माननीय
श्री शिवराजसिंह चौहान को हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री जगदीश कन्नौज
(बैंक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सह.)
श्री के. पाटनकर
(उपायुक्त सहकारिता)
श्री ए.के. हरसोला
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
श्री गजेन्द्र अत्रे
(वित्त प्रबंधक)
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण
सौजन्य से
श्री शिवकुमार वर्मा (शा.प्र. छनेरा)
श्री माँगीलाल शर्मा (पर्य. छनेरा)
श्री चम्पालाल कास्दे (शा.प्र. पंधाना)
श्री ओ.पी. यादव (शा.प्र. कालमुखी)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. आशापुर, जि.खंडवा
श्री संतोष कुमार शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. छनेरा, जि.खंडवा
श्री संतोष कुमार शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरूड़, जि.खंडवा
श्री संतोष कुमार शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. रेवापुर, जि.खंडवा
श्री प्रहलाद नामदेव (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बेड़ियाखुर्द, जि.खंडवा
श्री माँगीलाल शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरीसराय, जि.खंडवा
श्री माँगीलाल शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. दगड़खेड़ी, जि.खंडवा
श्री माँगीलाल शर्मा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. झमलानी, जि.खंडवा
श्री चन्दूलाल कटारे (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सड़ियापानी, जि.खंडवा
श्री कैलाश पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. घाटाखेड़ी, जि.खंडवा
श्री धनसिंह परिहार (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. आरूद, जि.खंडवा
श्री तेजसिंह गौर (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. दीवाल, जि.खंडवा
श्री आर.डी. पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. पंधाना, जि.खंडवा
श्री आर.डी. पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. सैय्यदपुर, जि.खंडवा
श्री शोभाराम मेहरा (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहना, जि.खंडवा
श्री प्रकाश मुहीराज (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. कालमुखी, जि.खंडवा
श्री शोभाराम पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. दुगवाड़ा, जि.खंडवा
श्री धन्नालाल पटेल (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. चिचगोहन, जि.खंडवा
श्री शिवानी गौर (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. खुटला, जि.खंडवा
श्री नवेद मलिक (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. अटूटखास, जि.खंडवा
श्री विनय सातले (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोराड़ीमाल, जि.खंडवा
श्री जितेन्द्र यादव (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. फिफराड़, जि.खंडवा
श्री नवेद मलिक (प्रबंधक)
सेवा सहकारी संस्था मर्या. अत्तर, जि.खंडवा
श्री मुरार पाटिल (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

निम्न-उच्च दाब एवं कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में निम्न दाब, उच्च दाब एवं कृषि पंप कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कंपनी ने कहा है कि एक जून से इन कनेक्शनों के लिए ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने कहा है कि इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं । निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित कार्मिको के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रबंध संचालक ने कहा कि वितरण केंद्र/ ज़ोन कार्यालय में यदि ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति नवीन बिजली कनेक्शन के लिए ऑफलाइन आवेदन लेकर आता है तो संबंधित वितरण केंद्र/ज़ोन प्रभारी सम्बंधित व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इ

रतलाम बैंक कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन राहत कोष में दिया

रतलाम। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न महामारी से निपटने के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रतलाम एवं इससे संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा अपने एक दिवस के वेतन की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायतार्थ दी गई। उक्त राशि 2 लाख 72 हजार 324 रु. का चेक बैंक कर्मचारियों द्वारा अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े को सौंपा गया। श्रीमती भिड़े ने बैंक कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर बैंक प्रशासक श्री पी.एन. गोडरिया, महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार जैन, बैंक कर्मचारी सर्वश्री राजेन्द्र कुमार मारू, शैलेष खरे, सुरेश परासिया, नागेश्वर बैरागी आदि उपस्थित थे। उक्त जानकारी बैंक के जनसंपर्क अधिकारी श्री सुशील कुमार शर्मा ने दी।

खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों के लिए उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में उच्चतम वृद्धि नाइजरसीड (755 रुपये प्रति क्विंटल) और उसके पश्चात तिल (370 रुपये प्रति क्विंटल), उड़द (300 रुपये प्रति क्विंटल) और कपास (लंबा रेशा) (275 रुपये प्रति क्विंटल) प्रस्तावित है। पारिश्रमिक में अंतर का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है।

खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

क्र.	फसलें	प्रस्तावित लागत केएमएस 2020-21	खरीफ के लिए एमएसपी 2020-21	एमएसपी में वृद्धि (पूर्ण)	लागत पर प्रतिफल (% में)
1	धान (सामान्य)	1,245	1,868	53	50
2	धान (ग्रेड ए)	-	1,888	53	-
3	ज्वार (हाइब्रिड)	1,746	2,620	70	50
4	ज्वार (मालदंडी)	-	2,640	70	-
5	बाजरा	1,175	2,150	150	83
6	रागी	2,194	3,295	145	50
7	मक्का	1,213	1,850	90	53
8	तूर (अरहर)	3,796	6,000	200	58
9	मूँग	4,797	7,196	146	50
10	उड़द	3,660	6,000	300	64
11	मूंगफली	3,515	5,275	185	50
12	सूरजमुखी बीज	3,921	5,885	235	50
13	सोयाबीन (पीला)	2,587	3,880	170	50
14	तिल	4,570	6,855	370	50
15	नाइजरसीड	4,462	6,695	755	50
16	कपास (मध्यम रेशा)	3,676	5,515	260	50
17	कपास (लंबा रेशा)	-	5,825	275	-

फलदार पौध रोपण के निर्देश

विदिशा। जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्मय से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान जिस प्रकार जल संचय रचनाओं का निर्माण अधिक से अधिक कराया जा रहा है ठीक वैसे ही प्रत्येक क्लस्टर में एक-एक फलदार पौधे रोपित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से लेने की हिदायत उन्होंने परियोजना अधिकारियों को दी है।

प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तरप्रदेश रोजगार कार्यक्रम शुरू किया

लखनऊ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उत्तरप्रदेश आपदा को अवसर में बदलने में सफल रहा है। संकट में साहस और सूझबूझ दिखाने वाले को सफलता मिलती है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम चाहे जनप्रतिनिधि हों या कर्मचारी हों सभी ने सराहनीय कार्य किया है।

प्रधानमंत्री ने यह विचार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के अन्तर्गत 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम' के शुभारम्भ अवसर पर अपने सम्बोधन में व्यक्त किये। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने रिमोट से अनावरण कर 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम' का शुभारम्भ किया। इस मौके पर लॉकडाउन तथा अनलॉक की कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी से सम्बन्धित एक फिल्म भी प्रस्तुत की गयी।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना संकट के दौरान पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उन्होंने 'जान भी, जहान भी' का मंत्र दिया। इसी क्रम में उनके मार्गदर्शन में 'आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम' का शुभारम्भ हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत रखोना, विकास खण्ड शिवपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री तिलक राम, जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड नौगढ़, ग्राम पंचायत कोडरा ग्रांट के श्री कुर्बान अली, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पाली, ग्राम पंचायत टिकरिया खोर के श्री नागेन्द्र सिंह से भी संवाद किया। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद, निदेशक सूचना श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ का ऑनलाइन भुगतान

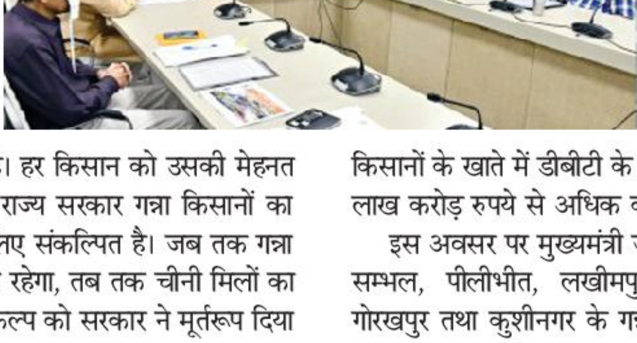

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शासन की कार्य पद्धति स्वयं की नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि का कारण बननी चाहिए। वर्तमान सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हर किसान को उसकी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होना चाहिए। राज्य सरकार गन्ना किसानों का पाई-पाई का भुगतान करने के लिए संकल्पित है। जब तक गन्ना किसानों के खेतों में एक भी गन्ना रहेगा, तब तक चीनी मिलों का संचालन भी होता रहेगा। इस संकल्प को सरकार ने मूर्तरूप दिया है।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को एक लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य के ऑनलाइन भुगतान कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ 01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रेषित की गयी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, सम्भल, पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, गोरखपुर तथा कुशीनगर के गन्ना किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर गन्ना विकास राज्यमंत्री श्री सुरेश पासी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
अन्तराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर
माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान
को हार्दिक शुभकामनाएँ
श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक)
श्रीमती भारती शेखावत
(उपायुक्त सहकारिता)
श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से
श्री उदयेन्द्रसिंह राठौर (शा.प्र. नागदा), श्री ओमप्रकाश चौहान (शा.प्र. कानवन)
श्री बालकृष्ण सोलंकी (शा.प्र. बदनावर), श्री विनायक शर्मा (पर्यवेक्षक बदनावर)
श्री राजेन्द्र वर्मा (शा.प्र. केसूर), श्री बाबूलाल रघुवंशी (पर्यवेक्षक केसूर)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. नागदा, जि.धार
श्री उदयेन्द्र सिंह राठौर (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सन्दला, जि.धार
श्री दिनेश उपाध्याय (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मनासा, जि.धार
श्री राधेश्याम यादव (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. धारसीखेड़ा, जि.धार
श्री ओमप्रकाश दशोरे (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पलवाड़ा, जि.धार
श्री बाबूलाल रघुवंशी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. ढोलाना, जि.धार
श्री भरतलाल शर्मा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. कानवन, जि.धार
श्री ओमप्रकाश चौहान (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. घटगारा, जि.धार
श्री गोपाल सिसोदिया (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गाजनोद, जि.धार
श्री सदाशिव पाटीदार (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. कठोडिया, जि.धार
श्री शंकरदास बैरागी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. रेशमगारा, जि.धार
श्री शरद गेहलोत (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बखतगढ़, जि.धार
श्री धनपालसिंह चौहान (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बदनावर, जि.धार
श्री विनायक शर्मा (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. केसूर, जि.धार
श्री बाबूलाल रघुवंशी (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. राठी बड़ौदा, जि.धार
श्री यशवंतसिंह (प्रबंधक)
आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खाचरोदा, जि.धार
श्री महेश जोशी (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

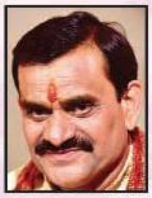

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बधाइयाँ

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री एम.एल. गजभिये
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री एस.के. खरे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

सौजन्य से

श्री कमल किशोर मालवीय (शा.प्र. साँवेर) श्री ओमप्रकाश चौहान (शा.प्र. क्षिप्रा, इंदौर) श्री सुरेश सोलंकी (शा.प्र. मांगल्या)
श्री तेजराम मालवीय (पर्य. साँवेर) श्री हरीश पाण्डेय (पर्यवेक्षक क्षिप्रा, इंदौर) श्री धर्मेन्द्र चौहान (पर्य. मांगल्या)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पाचोला, जिला इंदौर
श्री तेजराम मालवीय (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजोदा, जिला इंदौर
श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुडाना, जिला इंदौर
श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. दर्जी कराड़िया, जिला इंदौर
श्री जितेन्द्र राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सांवेर, जिला इंदौर
श्री सुनेरसिंह यादव (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ोदिया खान, जिला इंदौर
श्री जगदीश सोलंकी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. जामोदी, जिला इंदौर
श्री सुरेशचंद्र पिड़लाया (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोलसिन्दा, जिला इंदौर
श्री रामलाल वर्मा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुर्वार्डा हप्पा, जिला इंदौर
श्री कपिल राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. डकाच्या, जिला इंदौर
श्री माखनलाल पटेल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या.गुराण, जिला इंदौर
श्री विजयसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या.बरलाई, जिला इंदौर
श्री विजयसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पलासिया, जिला इंदौर
श्री लाखनसिंह कुशवाह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. मांगल्या सड़क, जिला इंदौर
श्री धर्मेन्द्र चौहान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. टोड़ी, जिला इंदौर
श्री अजबसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कदवालीखुर्द, जिला इंदौर
श्री कल्याणसिंह बारोड (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू होगी 'गोधन न्याय योजना'

पशु पालकों को लाभ दिलाने गोबर खरीदेगी सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम तथा सड़कों एवं शहरों में जहां-तहां आवारा घुमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय सभा कक्ष में ऑनलाईन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की इस अभिनव योजना की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते डेढ़ सालों में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मण्डलीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल शामिल किए गए हैं। यह मंत्री मण्डलीय समिति राज्य में किसानों, पशुपालकों, गौ-शाला संचालकों एवं बुद्धिजीवियों के सुझावों के अनुसार आठ दिवस में गोबर क्रय का दर निर्धारित करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सिंचाई रकबा के लिए 93.20 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए अधोसंरचना निर्माण के साथ ही सभी जरूरी संसाधन मुहैया करा रही है। इसी क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए 93 करोड़ 20 लाख 52 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। सिंचाई विस्तार का यह कार्य पूर्ण होने से लगभग 8594 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड छुईखदान की सुरही जलाशय के वेस्ट वियर की ऊंचाई बढ़ाने, नहर विस्तार का जीर्णोद्वार और लाईनिंग कार्य, नहर विस्तार तथा मुख्य नहर, लघु नहरों का जीर्णोद्वार एवं लाईनिंग कार्य के लिए 45 करोड़ 99 लाख 48 हजार रूपए और आमनेर-मोती नाला डायवर्सन योजना के जल संवर्धन का कार्य एवं नहरों का रिमॉडलिंग तथा लाईनिंग कार्य हेतु 47 करोड़ 21 लाख चार हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

सहकारी शकर कारखानों की समीक्षा

रायपुर। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रदेश में संचालित चार शकर कारखानों के काम-काज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए सभी प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया कि कारखानों में किसानों का गन्ना समय पर आए, शकर उत्पादन (रिकव्हरी) में वृद्धि हो इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने आगामी सीजन में 11 प्रतिशत शकर रिकव्हरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। डॉ. टेकाम ने कहा कि राज्य में शकर कारखाना लगाने का उद्देश्य किसानों को गन्ने की फसल से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि कारखाना लाभ में हो ताकि किसानों को उनके गन्ने का भुगतान समय पर होने के साथ ही उन्हें लाभांश का भी फायदा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को शकर कारखाने को समय पर व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने के लिए कैलेण्डर तैयार करने के भी निर्देश दिए।

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण ● खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड ● कृषि यंत्र के लिए ऋण ● दुग्ध डेयरी योजना

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मध्यप्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर श्री शिवराजसिंह चौहान को हार्दिक शुभकामनाएँ

श्री जगदीश कन्नौज (प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री अम्बरीश वैद्य (उपायुक्त सहकारिता झाबुआ)

श्री बी.एस. कोठारी (उपायुक्त सहकारिता अलीराजपुर)

श्री गणेश यादव (संभागीय शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक इंदौर)

श्री डी.आर. सरोठिया (वरिष्ठ महाप्रबंधक)

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से

श्री देवेन्द्र मिश्रा (शा.प्र. पेटलावद), श्री कमलेश ओझा (पर्यवेक्षक पेटलावद)
श्री देवीसिंह कलमे (शा.प्र. रायपुरिया), श्री दिनेश खतेड़िया (पर्यवेक्षक रायपुरिया)
श्री आशीष माहेश्वरी (शा.प्र. पारा), श्री नारायण हरसोला (पर्यवेक्षक पारा)
श्री आर.एस. बारिया (शा.प्र. उदयगढ़), श्री तेजबहादुर सिंह (पर्यवेक्षक उदयगढ़)
श्री गणपत सोनवाने (शा.प्र. जोबट), श्री महिपालसिंह राणावत (पर्यवेक्षक जोबट)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पेटलावद, जि.झाबुआ
श्री कमलेश ओझा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. टेमरिया, जि.झाबुआ
श्री रमेश राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रायपुरिया, जि.झाबुआ
श्री भागीरथ पाटीदार (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बेकल्दा, जि.झाबुआ
श्री भँवरसिंह चौहान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. मोहनकोट, जि.झाबुआ
श्री रमेशचंद्र पाटीदार (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरवेट, जि.झाबुआ
श्री अन्नूसिंह गामड़ (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. उदयगढ़, जि.झाबुआ
श्री राजेन्द्र राठौड़ (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बोरी, जि.झाबुआ
श्री मगनसिंह चौहान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. काकनवाड़ा, जि.झाबुआ
श्री मगनसिंह चौहान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुंडलवासा, जि.झाबुआ
श्री विजय गाँधी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पारा, जि.झाबुआ
श्री रणवीर सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पीथनपुर, जि.झाबुआ
श्री नारायण हरसोला (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रजला, जि.झाबुआ
श्री राजेंद्र मिश्रा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. खरडूबड़ी, जि.झाबुआ
श्री माँगीलाल चोपड़ा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. जोबट, जि.झाबुआ
श्री महिपालसिंह राणावत (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ी खट्टाली, जि.झाबुआ
श्री राजेश बघेला (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ागुड़ा, जि.झाबुआ
श्री जुवानसिंह मंडलोई (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कनवाड़ा, जि.झाबुआ
श्री भैरोसिंह डोडिया (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

● आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक'
अध्यक्ष : म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद
376, म.गाँ. मार्ग (बड़े गणपति के पास), इंदौर
फोन : 0731-2414181, मो. 9755014181

मेष

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा।

वृषभ

विपरीत समय में परिजन का भरपूर सहयोग मिलेगा। मेहनत व परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। किसी अप्रिय घटना की आशंका है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। यात्रा का जोखिम न लें।

मिथुन

सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आवक बढ़ेगी। तय किए गए लक्ष्य प्राप्त होंगे। सरकारी कर्मचारी लाभ प्राप्त करेंगे। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

कर्क

आलस्य का अनुभव करेंगे। नकारात्मकता को हावी न होने दें। कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। पिता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा।

सिंह

कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों का कार्य में सहयोग मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शुभ प्रवास होगा।

कन्या

दैनिक कार्य आसानी से हो जाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रतिस्पर्धी निराश होंगे। वित्तीय पक्ष उत्तम।

तुला

बनते काम रुक सकते हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शत्रु हावी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय उपयुक्त है। सरकारी कामकाज बनेंगे। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रवास शुभ।

वृश्चिक

विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। प्रतिभा के बल पर सफलता के नित नए आयाम को स्पर्श करेंगे। धन की आवक खुलेगी। वाणी माधुर्य का लाभ मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी।

धनु

राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य संबंध मधुर बनेंगे। मित्रों के सहयोग से योजना सफल होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन में विशेष ध्यान देना होगा। दुर्घटना का भय है।

मकर

यह माह अत्यधिक खर्च और व्यर्थ की भागदौड़ के साबित होगा। आपकी परिवार के लोगों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और धनलाभ के योग बनेंगे। अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें।

कुम्भ

घर परिवार में सुख शांति रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। साझेदारी में लाभ मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नवीन वस्त्र क्रय करने का मन बनेगा। सेहत से समझौता न करें।

मीन

नौकरी के कार्य से यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। युवा वर्ग समय का सदुपयोग करेंगे। पुराने मित्र से मिलने पर मन प्रसन्न होगा। ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखें।

'फेयर' शब्द हटाने पर जताई बिपाशा ने खुशी

हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. ने अपनी फेयरनेस क्रीम फेयर एंड लवली के नाम से 'फेयर' शब्द हटाने का फैसला किया था। बॉलीवुड हस्तियों बिपाशा बसु, ऋचा चड्ढा और अभय देओल ने कंपनी के इस फैसले को सराहा है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान का जमकर सपोर्ट किया जा रहा है। बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे अपने सांवले रंग को लेकर कई बातें सुनने को मिली। पिछले 18 सालों में कई बड़े बजट के स्किन केयर एंडोर्समेंट के मुझे ऑफर मिले लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर अड़ी रही। इसे रोकने की जरूरत है। ये एक झूठा सपना है, जिसे हम बेच रहे हैं कि सिर्फ फेयर ही लवली है और खूबसरत भी। अभय देओल ने लिखा, ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान ने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया था। आप सब इस जीत के हकदार हैं जिन्होंने इस तरह की फेयरनेस क्रीम की बिक्री और विज्ञापनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, उन नियमों को तोड़ने के लिए जो सुंदरता को परिभाषित करते रहे हैं। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने साल 2015 में अपनी टीशर्ट पर 'नॉट फेयर बट लवली' प्रिंट करवाया था। रिचा ने इस फेयरनेस क्रीम के नाम में से फेयर शब्द हटाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा सब चीजों को बदलने में समय लगता है, हमें अपने रंग पर गर्व होना चाहिए।

सुशांत की आत्महत्या पर कंगना का गुस्सा

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने बॉलीवुड ने भारी उथल-पुथल मचा दी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मायानगरी में बैठे फिल्मी दुनिया के लोग बाहरी लोगों की परवाह नहीं करते हैं। इस विवाद पर अभिनेत्री कंगना रानौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद पर फिर भड़ास निकाली है। कंगना रानौत की टीम की ओर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं, सुशांत की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन कुछ लोग इस मामले में माहिर हैं कि किस तरह का नैरेटिव चलाना है। वे बता रहे हैं कि कुछ लोगों का दिमाग कमजोर होता है, वे डिप्रेशन में आ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सुशांत इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के रैंक होल्डर थे। उनका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है।

कंगना आगे कहती हैं, अपने इंटरव्यू में वह साफ कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं इंडस्ट्री अपनाती है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। क्या इन बातों में इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है। वाहियात फिल्मों को सारे अवॉर्ड मिलते हैं। काय पो छे जैसी फिल्म से सुशांत ने डेब्यू किया, लेकिन उन्हें कोई अवॉर्ड नहीं मिला। छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्म को कोई पूछता नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम जो करते हैं, उसे आप स्वीकारते क्यों नहीं हैं। खुद मैं जिन फिल्मों को डायरेक्ट करती हूं, सुपरहिट फिल्म को ये लोग फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पर छह मुकदमे क्यों किए गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई है।

सभी फसलों के लिए उपयोगी
गंगा एवं
जय जवान
सिंगल सुपर फॉस्फेट (रत्नम)
NPK मिक्स फर्टिलाईजर
12:32:06 • 20:20:10
08:32:08 • 15:15:7½
देवपुत्र®
सभी फसलों का उत्कृष्ट प्रमाणित बीज
सिंगल सुपर फॉस्फेट (रत्नम)
कार्बनिक खाद मिश्रण
सिटी कम्पोस्ट | वर्मी कम्पोस्ट
ऑर्गेनिक मेन्यूअर | प्रॉम खाद
रत्नम
जिंक सल्फेट 21%
सिंगल सुपर फॉस्फेट
(पावडर एवं दानेदार)
NPK मिक्स फर्टिलाइजर
12:32:06 • 20:20:10
08:32:08 • 15:15:7½
सभी सहकारी समितियों एवं विपणन संघ केन्द्रों पर उपलब्ध
दिव्यज्योति एग्रीटेक प्रा.लि.
चातक एग्रो (इं) प्रायवेट लिमिटेड
बालाजी फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड
305, उत्सव एवेन्यू, 12/5, उषागंज (जावरा कम्पाउण्ड), इन्दौर (म.प्र.)
फोन: 0731-4064501, 4087471, मोबाइल: 98272-47057, 98270-90267, 94251-01385

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक बृजेश त्रिपाठी द्वारा वी.एम. ग्राफिक्स, के-29, एलआयजी कॉलोनी, इंदौर से मुद्रित एवं 306-ए ब्लॉक, शहनाई-II, रेसीडेन्सी कनाड़िया रोड, इन्दौर से प्रकाशित (फोन : 0731-2595563, 9752558186, 8989179472, संपादक : बृजेश त्रिपाठी, प्रकाशन दिनांक : 17